सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 161, नई दिल्ली । बुधवार, 21 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिये, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है।

03 एमसीडी का हिंदूराव अस्पताल बारिश से बदहाल

06 समय की सबसे बड़ी मांग अक्षय ऊर्जा

08 21 अगस्त को भारत बंद के मध्यनजर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित

क्या आप जानते हैं दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशेष परिवहन आयुक्त मिलकर दिल्ली परिवहन विभाग को तकनीकी से गैर तकनीकी बनाने के लिए कार्यरत हैं

संजय बाटला

नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं दिल्ली में किस भारी वाहन चालक को लाइसेंस जारी करना है इसका फैसला कौन करता है ?

क्या आप जानते हैं दिल्ली में चल रहे ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड वाहन स्किल टेस्ट सेंटर पर दिल्ली की जनता को प्राप्त होने वाला लाइसेंस कौन अप्रूव करता है ?

क्या आप जानते हैं दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड फिटनेस जांच प्रमाण पत्र कौन जारी करता है ?

क्या आप जानते हैं दिल्ली में चल रहे 13 क्षेत्रीय कार्यालय, डीटीओ मुख्यालय, एसटीए शाखा, आटो टैक्सी शाखा, झुलझुली वाहन जांच केन्द्र और बुराड़ी वाहन जांच केन्द्र के प्रबंधक पद पर किस तकनीकी अधिकारी को नियुक्त किया हुआ है और नियम के अनुसार किस का होना आवश्यक है ?

क्या आप जानते हैं दिल्ली में चल रहे ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग स्किल टेस्ट सेंटर पर किस तकनीकी अधिकारी को नियुक्त कर रखा है ?

भारी वाहन चालकों को ट्रैनिंग देने और उनका ड्राइविंग स्किल टेस्ट लेकर लाइसेंस जारी करने का कार्य दिल्ली में कौन करता है ?

अगर आप को यह पता लगे कि जनता की सुरक्षा के प्रति जो नियमानुसार लाइसेंस जारी करने, वाहन की फिटनेस जांच पड़ताल करने वाले एवम्क्षेत्रीय कार्यालयों में मुख्य अधिकारी गैर तकनीकी या नियम के समकक्ष योग्यता अनुसार नही है तो क्या दिल्ली की जनता अपने आप को सड़कों पर सुरक्षित समझती हैं ?

आप की जानकारी हेतु बता दें दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल, मुख्य सचिव को इन सभी बातों की पूर्ण जानकारी है की परिवहन विभाग में जिन अधिकारियों को जनता की सुरक्षा के विभागों/ शाखाओं में कार्य करने के लिए परिवहन आयुक्त/ विशेष परिवहन आयुक्त द्वारा आसीन किया हुआ है उनमें अधिकतर अधिकारी उन पदो पर आसिन होने योग्य नहीं हैं पर फिर भी आसीन है और कोई पूछने वाला नहीं, अर्थात प्रशासक द्वारा मूक अनुमति।

दिल्ली में वाहनों में महिला सुरक्षा के प्रति निर्भया हादसे पर दिए गए आदेश और दिशा निर्देश पैनिक बटन सेंटर निर्माण करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण खर्चा लेने के बाद भी दरकिनार कर विशेष परिवहन आयुक्त अपनी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कम्पनी डिम्ट्स को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू नही होने दे रहे और फिर भी कोई पूछने वाला नहीं यानी प्रशासक की मूक अनुमति।

आपकी जानकारी हेतु बता दें परिवहन विभाग में आज की तारीख में मात्र

2 स्थाई एमएलओ है जिनमे से एक को गैर तकनीकी पद पर आसीन किया हुआ है।

20 तकनीकी शाखाओं में जहा सभी पर एमएलओ की नियुक्ति नियम अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार होनी चाहिए वहा पर मात्र एक एमएलओ की नियुक्ति ?

क्षेत्रिय शाखा संख्या

1,2,3,6 पर सैक्शन अधिकारी को नियुक्त किया हुआ है जो गैर तकनीकी अधिकारी है

4,5,10,11 पर पीसीओ को नियुक्त किया हुआ है

8,9,12 पर एमवीआई को नियुक्त किया हुआ है

डीटीओ मुख्यालय, आटो टैक्सी शाखा एवम् झूलझूली वाहन जांच शाखा पर एमवीआई को नियुक्त कर रखा है और

बुराड़ी वाहन जांच शाखा पर पीसीओ को नियुक्त कर रखा है।

अब भारत सरकार, एवम्दिल्ली की जनता स्वयं फैसला करे कि

"दिल्ली में वाहनों से होने वाले हादसो का असली जिम्मेदार कौन ?" नुकसान भी जनता का और ज़िम्मेदारी भी जनता की, कहा का और कैसा है यह न्याय, बड़ा सवाल !

"और सब कुछ देखते हुए भी भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, उपराज्यपाल दिल्ली, उच्च न्यायालय एवम्मुख्य सचिव चुप,"

रक्षाबंधन की शाम मेट्रो में उमड़ी भीड़, रेड लाइन पर सेवा प्रभावित

सोमवार को रक्षा बंधन के दिन दिल्ली मेट्रो में जहां यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई वहीं पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। मेट्रो की रेड लाइन पर कुछ देर के लिए सेवा प्रभावित रही तो वहीं पर नमो भारत ट्रेन में 32 हजार से ज्यादा लोगों ने एक दिन में सफर किया।

नई दिल्ली। रक्षा बंधन के कारण सोमवार को मेट्रो में यात्रियों की भीड़ अधिक रही। इस वजह से कई स्टेशनों पर यात्रियों की काफी भीड़ देखी गई। इस वजह से सामान्य दिनों के मुकाबले मेट्रो में अधिक यात्रियों ने सफर किया। स्थिति यह है कि देर रात भी मेट्रो में व्यस्त समय की तरह भीड़ रही।

दिन में मेट्रो का परिचालन सामान्य रहा लेकिन देर रात रेड लाइन पर तकनीकी कारणों से मेट्रो का परिचालन थोड़ी प्रभावित हुई। इससे यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्टेशनों पर मेट्रो देर तक रुक-रुक कर चली।

रेड लाइन के कश्मीरी गेट पर मेट्रो करीब 15 मिनट खड़ी रही। इसके बाद कश्मीरी गेट से शास्त्री पार्क स्टेशन के बीच मेट्रो की रफ्तार धीमी रही। रक्षा बंधन के मद्देनजर

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएम आरसी) ने अतिरिक्त मेट्रो तैयार रखी थी। बताया जा रहा है सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक मेट्रो ट्रेनों का परिचालन हुआ।

बता दें देश के पहले दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का परिचालन वर्तमान में साहिबाबाद से मेरठ साउथ के बीच किया जा रहा है।

गाजियाबाद में रहने वाले हजारों लोग रोजाना नौकरी के लिए नोएडा दिल्ली और हरियाणा तक आवागमन करते हैं। नमो भारत ट्रेन के गाजियाबाद स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है इससे राजधानी में आवागमन सुगम है।

सोमवार को रक्षाबंधन पर रात नौ बजे तक रिकॉर्ड 32 हजार से अधिक यात्रियों ने नमो भारत ट्रेन में सफर किया। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान एक दिन में सबसे अधिक 27 हजार यात्रियों ने सफर किया था।

ट्रैफिक पुलिस का आश्वासन जल्द ही सदर बाजार की जाम की समस्या को हल करेंगे

सुषमा रानी

पुरानी दिल्ली स्थित सदर बाजार में जाम लगना आम बात हो गई है इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ट्रैफिक पुलिस को यातायात जाम के विरोध में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों व फेडरेशन के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई। इसमें ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर मदन मोहन सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे फेडरेशन की ओर चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा व अध्यक्ष राकेश यादव, वाइस चेयरमैन खंडेलवाल, महासचिव सतपाल सिंह मांगा, कमल कुमार, कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाकिर भाई, उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता सहित अनेक व्यापारी नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने ट्रैफिक अधिकारियों को बताया आए दिन ट्रैफिक जाम के कारण कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है. हालत यह है कि रात को भी बाजार से निकलना मुश्किल हो गया है. प्रमुख चौक-चौराहों से लेकर अंदर गलियों तक जाम लग रहा है. गोदाम से दुकान तक सामान ढुलाई में लगे ठेलों की लंबी लाइन लग जाती है क्योंकि आगे चौराहों पर ऑटो और ई-रिक्शा की वजह से जाम लग जाता है. व्यापारियों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस नदारद रहती है, जिसकी वजह से पूरे बाजार में जाम

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि रात को दुकान बंद करने के बाद व्यापारियों को घर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वहीं ग्राहकों को आने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस जाम की वजह से कई ग्राहकों के जेब भी कट जाते हैं. उन्होंने कहा कि सदर बाजार के 12 टूटी, कुतब रोड, सिंगाड़ा चौक, सदर थाना चौक, पुल मिठाई रोड आदि इन सभी जगहों पर जाम लगा रहता है. वहीं दूसरी और सदर बाजार थाने से लेकर 12 टूटी चौक तक एमसीडी द्वारा पार्किंग दी हुई वह दो-दो तीन-तीन लेने गाड़ियां लगा देता है। इसके कारण भी काफी जाम रहता है। साथ ही फेडरेशन व ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने पूरे सदर बाजार का राउंड लिया और व्यापारियों ने अपनी दिक्कत के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी।

इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को 15 दिन 15 दिन का समय देते हुए कहा के अगर इस समय ट्रैफिक समस्या हल हो गई तो फेडरेशन प्रदर्शन नहीं करेगी। वरना सड़कों पर उतर के ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।

इस सॉफ्टवेयर पर ट्रैफिक एक्सपेक्टेड मदन मोहन ने कहा कि ई-रिक्शाओं की समस्या हल करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी जरूरत है। कहीं ईरिक्शा बिना नंबर के और इनका जितना मर्जी चालान कर ले यह वह चालान भी नहीं भरते और रोड़ों पर रहते हैं। इसके साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि हर चौक पर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही सुबह 10:00 से 1:00 तक और शाम को 5:00 से 8:00 तक तैनात रहेगा। उसके साथ-साथ हमें नगर निगम और लोकल पुलिस का भी सहयोग चाहिए जिसमें अवैध पटरी से बी काफी ट्रैफिक जाम की दिक्कत आती है।

इस अवसर पर कमल कुमार व दीपक मित्तल ने का आने वाले समय में व्यापारियों के त्यौहार एक सीजन है। अगर ट्रैफिक की समस्या रही तो यहां पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों को रेल भाडे में छूट दी जाए:पेंशनर्स

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। भारतीय पेंशनर्स मंच के अध्यक्ष वी एस यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर भारतीय रेल में यात्रा करने वाले सिनीयर सिटीजन से छीनी गई रेल भाडे की रियायतों को पुनः बहाल करने की मांग की है। भारतीय पेंशनर्स मंच के अध्यक्ष वी एस यादव ने बताया कि कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिको को रेल भाडे में मिलने वाली रियायते वापस ले ली थी। तब सरकारी तौर पर यह कहा गया था कि भारतीय रेलवे की सेवाए सामान्य होते ही सिनीयर सिटीजन को रेल भाडे में मिलने वाली छूट को बहाल कर दिया जाएगा।श्री यादव ने कहा कि कोविड को खत्म हुए करीब चार साल होने को है मगर सरकार से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई जवाब नही मिला है। पेंशनर्स मंच के मुताबिक संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट में ट्रेनों में साधारण चेयर कार,स्लीपर क्लास,एसी थर्ड स्लीपर और एसी चेयर कार में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिको के लिए रियायत बहाल करने की सिफारिश भी कर दी है। मंच ने रेलवे को चेताया कि वरिष्ठ नागरिक इंडिगो,एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस द्वारा किराये में दी जाने वाली रियायतों का लाभ उठा रहे हैं। और ट्रेन की यात्रा से बचते हुए हवाई जहाज से यात्रा कर रहे है। जिससे भारतीय रेल को राजस्व का नुकसान हो रहा है। यादव ने बताया कि वरिष्ठ नागरिको को कुछ राज्य परिवहन की बसों तक में भाडे में छूट दी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि पैंशन पर रहने वाले वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओ की आसमान छूती कीमतो और मुद्रास्फीति के इस दौर में यात्रा करने के लिए पूरा किराया देने में असमर्थ है। किराए की वजह से वरिष्ठ नागरिक की जेब अलाव नहीं कर पाती है। दूसरे सरकार के नारे ₹एक भारत श्रेष्ठ भारत₹ के तहत भारत के सभी पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा करवाने का सरकारी उदेश्य भी प्राप्त हो सकता है। मंच के अध्यक्ष ने भारत सरकार से एक बार फिर गुहार की है कि वह वरिष्ठ नागरिक को रेल किराए में रियायतें तत्काल बहाल करने के आदेश जारी करे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

22-23 तारीख को ऑटो-टैक्सी चालकों की हड़ताल राजधानी में चरमरा सकती है परिवहन व्यवस्था

संजय बाटला

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अगर आप 22–23 तारीख को घर से बाहर कहीं निकलते हैं तो अपनी गाड़ी का इंतजाम खुद ही कर लें। क्योंकि ये दो दिन टैक्सी और ऑटो चालकों की हड़ताल है। जिस कारण से आपको भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। दो दिनों तक करीब सड़कों से चार लाख गाड़ियों के ना उतरने की आशंका है।

नई दिल्ली। दो दिन बाद यानि बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में कहीं निकलना हो तो पूरी तैयारी के साथ निकले अन्यथा ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल आपके बीच रास्ते परेशान कर सकती है। गंतव्य तक जाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

दो दिन के लिए ऑटो टैक्सी चालकों ने बुलाई हड़ताल

यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 22 और 23 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के ऑटो टैक्सी चालकों ने हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान दो दिनों तक तकरीबन चार लाख परिवहन वाहनों के सड़कों पर न उतरने की आशंका रहेगी। जिसमें ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवा भी प्रभावित रहेगी।

आशंका है कि टैक्सी, ऑटो चालकों की हड़ताल से दो दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी की परिवहन व्यवस्था चरमरा सकती है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक प्रमुख ऑटो, टैक्सी चालकों ने दो दिवसीय संयुक्त हड़ताल की घोषणा की है।

केंद्र और राज्य सरकार मनमाने पर नहीं लगा रही रोक-संगठन

आशंका है कि एक लाख ऑटो और चार लाख टैक्सियां जिनमें एक लाख से अधिक कैब हैं, वे नहीं चलेंगी। हड़ताल करने वाले संगठनों का आरोप है कि एक तरफ जहां ऐप आधारित कैब सेवा से ऑटो टैक्सी चालकों को नुकसान हो रहा है। वहीं, कैब चालकों का ऐप कंपनियां शोषण कर रही हैं उनसे मोटा कमीशन वसूल रही है।

इसी तरह, बाइक टैक्सी और ई-रिक्शा से भी उनके रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार इस मनमाने पर रोक नहीं लगा रही है। इसलिए चालकों के हित में उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है।

दिल्ली में 530 करोड़ रुपये में बन रहा अनोखा पार्क, एक तरफ बनारस तो दूसरी ओर दिखेगी पटना की झलक

दिल्ली नगर निगम द्वारा पंजाबी बाग में Bharat Vandana Park को विकसित किया गया है। यहां कबाड़ से विभिन्न राज्यों की ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिकृति का निर्माण किया गया है। वेस्ट टू वंडर पार्क सराय काले खां इस पार्क का विकास भी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया है। यहां भी कबाड़ से दुनिया की प्रमुख कलाकृतियों व स्मारकों की प्रतिकृति बनाई गई है।

पश्चिमी दिल्ली। जीवनदायिनी गंगा के किनारे बसा पटना हो या बनारस, दोनों शहरों की सांस्कृतिक समृद्धि यदि आपको राजधानी दिल्ली में महसूस करनी हो तो बस कुछ महीने और इंतजार कर लें।

द्वारका सेक्टर 20 में बन रहे भारत वंदना पार्क (Bharat Vandana Park) में आपको एक तरफ बनारस के सुंदर घाटों के किनारे विराजे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे तो चंद कदमों की दूरी पर यहीं पर्वतों से घिरे केदारनाथ मंदिर भी दिख जाएगा। करीब 200 एकड़ के प्रांगण में आपको यहां संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के दर्शन हो जाएंगे।

अंतिम चरण में निर्माण का काम

फिलहाल पार्क में निर्माण जोरों से चल रहा है। निर्माण के अंतिम चरण में आकर अब पार्क का भव्य आकार धीरे धीरे अपना भव्य रूप लेता जा रहा है। निर्माण कार्य की रफ्तार व जमीनी स्थिति को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि आने वाले चार महीने के भीतर यह पार्क पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा।

मिनी इंडिया की थीम पर तैयार हो रहा पार्क

मिनी इंडिया की थीम व कमल के आकार में डिजाइन किए गए और लगभग 200 एकड़ में फैले पार्क में इको जोन, जल निकाय, विभिन्न राज्यों की ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिकृतियां, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आपको पुराने संसद भवन की गोल इमारत की प्रतिकृति नजर आएगी। शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध,

पटना में लोकआस्था से जुड़ा प्रसिद्ध महावीर मंदिर की प्रतिकृति भी यहां आपका ध्यान खींच लेगी। जयपुर का हवा महल, कर्नाटक के हंपी का रथ मंदिर, एलोरा की गुफाएं, अंडमान का सेल्यूलर जेल सहित विभिन्न राज्यों की प्रसिद्धि से जुड़े तमाम इमारतों की प्रतिकृति यहां तैयार की जा रही है। अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकांश प्रतिकृति तैयार हो चुकी है।

समय से विलंब चल रही परियोजना

पार्क का निर्माण एनबीसीसी व डीडीए द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। पार्क के निर्माण कार्य की आधारशिला केंद्रीय मंत्री अमित शाह व हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में वर्ष 2019 में रखी गई थी। तब कहा गया था कि नवंबर 2022 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा।

इसकी कुल लागत करीब 530 करोड़ रुपये रखी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की दस्तक ने परियोजना के समय से पूरा होने पर ग्रहण लगा दिया। इसके बाद निर्माण कार्य सुस्त पड़ गई। बाद में समय समय पर इसके पूरा होने की समय सीमा को बढ़ाया गया।

बीच में इस बात की कोशिश की गई कि निर्माण कार्य को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूरा कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाए, लेकिन यह कोशिश पूरी नहीं हुई। अभी जमीनी स्थिति पर गौर करें तो आगामी चार महीने में इसके पूरा होने की संभावना दिख रही है।

डीडीए और एनबीसीसी तैयार करा रहा पार्क

मिनी इंडिया की थीम व कमल के आकार में डिजाइन किए गए और लगभग 200 एकड़ में फैले पार्क में इको जोन, जल निकाय, ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिकृतियां, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि शामिल होंगे। डीडीए और एनबीसीसी इसे संयुक्त रूप से तैयार करने में जुटे हैं।

स्काईवाक दिखाएगा ऊपर से पार्क का नजारा

यह पार्क करीब 10 अलग-अलग जोन में बंटा है। एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए आपको टॉय ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बैटरी चालित रिक्शे या बस भी यहां पर्यटकों को उपलब्ध होंगे।

पार्क का पूरा नजारा आप ऊपर से देख सकें, इसके लिए जगह जगह पीलर बनाए जा रहे हैं। इन पीलरों को पायलोन कहा जाता है। एक पायलोन दूसरे पायलोन से स्काई ब्रिज से जुड़ा होगा।

नौकायन की मिलेगी सुविधा

इस ब्रिज से आप पूरे पार्क का नजारा ऊपर से निहार सकेंगे। ऊपर से पार्क को निहारना आपको तब और खुशी देगा जब आप यहां भारत का पूरा मानचित्र देखेंगे। एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी इस पार्क में काफी कुछ है। पार्क के सरोवरों को पुष्पकृति सरोवर का नाम दिया गया है। यहां नौकायन की भी सुविधा होगी।

सोशल मीडिया और रिश्ते

--- संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल

सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया में,
रिश्तों की भी तस्वीरें बदल गई हैं।
लाइक्स और कमेंट्स की बौछार में,
हमने खुद की पहचान खो दी है।

हर सुबह की शुरुआत में,
चेक करते हैं हम अपनी फीड को।
क्या छूट गया, क्या नया आया,
अब रिश्ते भी उसी डिजिटल ट्रेंड को।

चेहरे के भाव अब इमोजी से सजते हैं,
हृदय की धड़कन भी स्टेटस बन जाते हैं।
फ्रेंड्स लिस्ट में रिश्ते ही लुढ़कते हैं,
जिनके बीच में फर्क साफ नजर आता है।

जब मिलते हैं हम ऑफलाइन,
नज़दीकियां खुद बेमानी लगती हैं।
लाइव चैट्स और वीडियो कॉल्स के बीच,
कभी बातें भी अधूरी लगती हैं।

सोशल मीडिया ने जो दिखाया,
क्या वो सच्चाई का हिस्सा है?
रिश्तों की गहराई और सच्चाई को,
क्या वो केवल एक मैट्रिक्स है?

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कदम उठाएगी केंद्र सरकार, जुर्माने की राशि होगी दोगुनी; स्पीड लिमिट पर भी चर्चा

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। स्कूल बसों में सफर करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा की चिंता करते हुए केंद्र सरकार ने कहा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय मोटर वाहन कानून में इस तरह के कुछ संशोधन की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जुर्माने की राशि दोगुनी की जा सकती है।

नई दिल्ली। स्कूल बसों में सफर करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा की चिंता करते हुए केंद्र सरकार इनसे जुड़े ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में और कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसके तहत जुर्माने की राशि दोगुनी की जा सकती है ताकि स्कूल बस चलाने वाले ड्राइवरों को उनकी ड्यूटी के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जा सके।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय मोटर वाहन कानून में इस तरह के कुछ संशोधन की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय को इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही एक समिति की सिफारिशों पर भी अमल करना है, जिसने सड़क सुरक्षा के संदर्भ में स्कूली बसों पर और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा की है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जुर्माने की राशि दोगुनी करने के पीछे मकसद है कि शैक्षणिक संस्थानों में संचालित की जा रही बसों के मालिकों को भी सख्त संदेश दिया जा सके।

बसों की फिटनेस परीक्षण में धांधली

रेड लाइट अनुचित तरीके से पार करना, सीमा से अधिक गति और लेन उल्लंघन जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण बड़े हादसे हो जाते हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि जागरूकता बढ़ाने के उपायों के साथ सख्त सजा का भय भी हो। बसों की फिटनेस परीक्षण में भी धांधली होती है। इसी तरह रोड परमिट के मामले में भी मनमानी की जाती है।

'स्पीड लिमिट में परिवर्तन करने की दी जाए छूट'

इन सभी विषयों को संशोधन के प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय हाईवे और एक्सप्रेस वे में स्पीड लिमिट को लेकर विशेषज्ञ समिति की इस सिफारिश पर भी अमल करने की तैयारी में है कि राज्यों को एनएचएआई के साथ परामर्श के बाद ही स्पीड लिमिट में कोई परिवर्तन करने की छूट होनी चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, मिंटो ब्रिज में ऑटो डूबा; जलभराव से कई इलाकों में जाम

दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। कुछ हिस्सों में बारिश भी शुरू हो गई है। इससे पहले सोमवार को रक्षाबंधन के दिन उमस रही। जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 .6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं पर न्यूनतम तापमान 27 .6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

नई दिल्ली। राजधानी में सोमवार को तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस वजह से दिन में उमस भरी गर्मी रही। हालांकि शाम को कुछ इलाकों में बहुत हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो-तीन दिन तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी।

अगले दो दिन भी हो सकती है वर्षा

मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा भी हो रही है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार को बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बुधवार व बृहस्पतिवार को भी हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है।

दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। शाम को पीतमपुरा में 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हुई।

लगातार 23वें दिन हवा 'संतोषजनक' श्रेणी में रही

दिल्ली में लगातार 23वें दिन हवा की गुणवत्ता संतोषजनक

श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी) के अनुसार मंगलवार को एयर इंडेक्स बढ़ सकता है। इस वजह से एयर इंडेक्स 100 से अधिक पहुंच सकता है। तीन दिन हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही सकती है।

सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 83, फरीदाबाद का 62, गाजियाबाद का 93 व नोएडा का एयर इंडेक्स 90 रहा। इस वजह से इन शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। ग्रेनो (Greater Noida) का एयर इंडेक्स 102 व गुरुग्राम का एयर इंडेक्स 141 रहा।

मंकीपॉक्स को लेकर अलर्ट हुई दिल्ली, AIIMS ने निर्धारित किए बेड; जारी की SOP

एम्स ने मंकीपॉक्स के लिए पांच बेड निर्धारित किया। वहीं कई देशों में एमपॉक्स वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एमपॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ के अधिकारी का बयान सामने आया था। अधिकारियों के अनुसार यह पुराना स्ट्रेन है यह कोई कोविड नहीं है। उनका कहना है कि इसके प्रसार को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स, AIIMS) ने मंकीपॉक्स (mpox outbreak india) के लिए पांच बेड निर्धारित किया। सफदरजंग को रेफरल अस्पताल बनाया गया है।

मंकीपॉक्स एक वायरल जूनोसिस है, जिसके लक्षण अतीत में चेचक के रोगियों में देखे गए लक्षणों के समान होते हैं, हालांकि चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर होते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मंकीपॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है, जिससे आगे प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने, तेजी से पहचान करने और कड़े संक्रमण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता होती है।

वहीं, यह एसओपी एम्स आपातकालीन विभाग में मंकीपॉक्स के मामलों को संभालने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करता है।

संदिग्ध मंकीपॉक्स के रोगियों को संभालने के लिए प्रोटोकॉल

1. ट्राइएज क्षेत्र में स्क्रीनिंग

आगमन पर, बुखार, दाने, या पुष्टि किए गए मंकीपॉक्स मामलों के संपर्क के इतिहास वाले रोगियों को तत्काल मूल्यांकन के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए।

प्रमुख लक्षणों को पहचानें-

बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द,

सूजी हुई लिम्फ नोड्स, ठंड लगना, थकावट, और विशिष्ट त्वचा के घाव (मैकुलोपापुलर दाने जो पुटिकाओं और फुंसियों में बदल सकते हैं)।

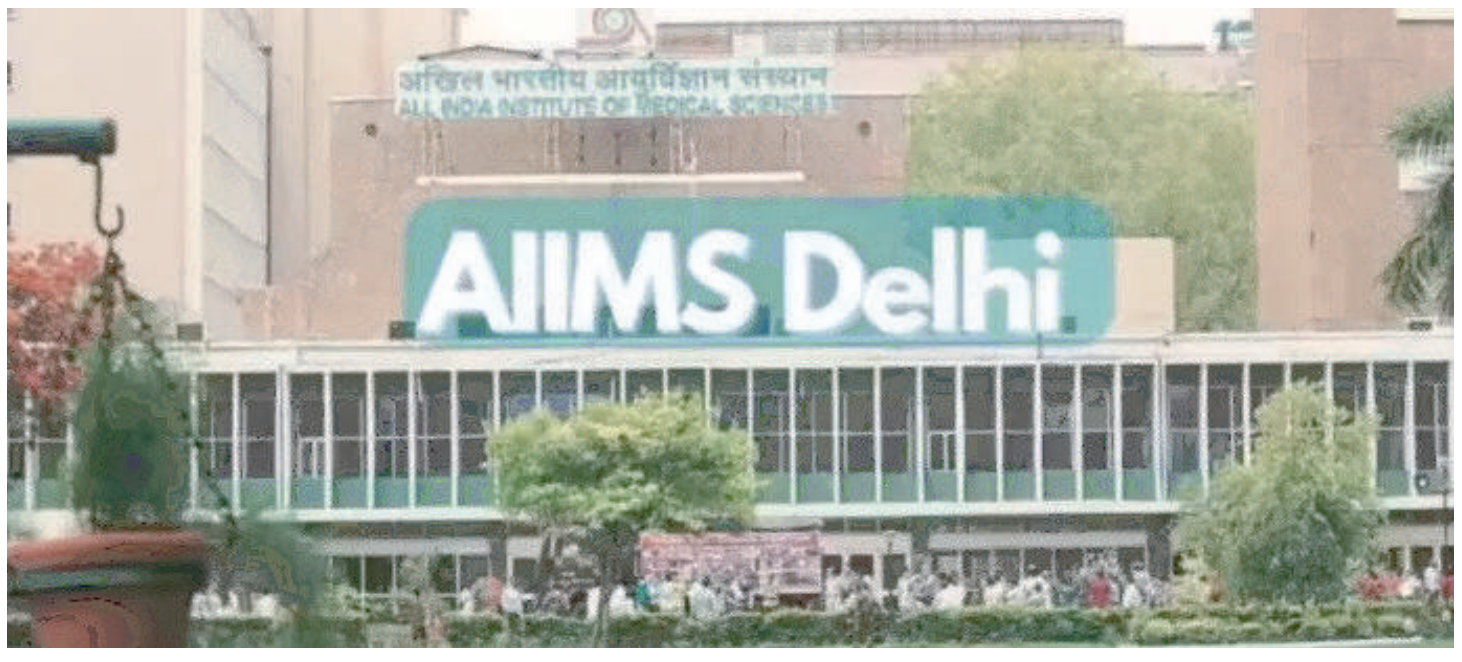

2. अलगाव/धारण क्षेत्र-

अन्य रोगियों और कर्मचारियों के साथ संपर्क को कम करने के लिए संदिग्ध रोगियों को तुरंत एक निर्दिष्ट अलगाव क्षेत्र में रखें।

ये बेड किए गए निर्धारित

एबी-7 बेड नंबर 33, 34, 35, 36 और 37 को मंकीपॉक्स के मरीजों को अलग करने के लिए रखा गया है। ये बिस्तर आपातकालीन सीएमओ की सिफारिश पर मंकीपॉक्स रोगियों को आवंटित किए जाएंगे और मेडिसिन विभाग द्वारा इलाज किया जाएगा। एबी-7 रोगी के लिए एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र रहेगा। जब तक कि उसे निश्चित देखभाल के लिए निर्धारित अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

3. आईडीएसपी को अधिसूचना-

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के अधिकारियों को संपर्क नंबर के साथ सूचित करें। किसी संदिग्ध मामले की पहचान होने पर 8745011784 उन्हें रोगी का विवरण, संक्षिप्त इतिहास, नैदानिक निष्कर्ष और संपर्क विवरण प्रदान करें।

4. सफदरजंग अस्पताल में रेफरल-

सफदरजंग अस्पताल को सूचित किया गया है, उसे मंकीपॉक्स रोगियों के प्रबंधन और उपचार के लिए नामित किया गया है। मंकीपॉक्स होने के किसी भी संदिग्ध को आगे के मूल्यांकन और उपचार के लिए सुरक्षित अस्पताल में भेजा जाना चाहिए।

5. एम्बुलेंस-

सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए एक समर्पित एम्बुलेंस आवंटित की गई है। आपातकालीन कर्मचारियों को संदिग्ध मंकीपॉक्स रोगी को सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए मोबाइल नंबर 89296838 पर एम्बुलेंस समन्वयक को सूचित करना होगा।

6. रोगी की देखभाल और अलगाव-

- सभी रोगियों को सख्त संक्रमण नियंत्रण उपायों के साथ संभाला जाना चाहिए।

- संदिग्ध मामलों में स्टाफ को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग करना चाहिए।

7. दस्तावेजीकरण और संचार-

- रोगी के विवरण, लक्षण और का उचित दस्तावेजीकरण।

कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले

दुनिया के कई देशों में एमपॉक्स वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब एमपॉक्स (monkey pox cases in india) को लेकर डब्ल्यूएचओ के अधिकारी का बयान सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, यह पुराना स्ट्रेन है, यह कोई कोविड नहीं है। उनका कहना है कि इसके प्रसार को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

डब्ल्यूएचओ के अधिकारी हंस क्लूज ने इसको लेकर कहा, ₹हम मिलकर एमपॉक्स से निपट सकते हैं और हमें मिलकर निपटना चाहिए।" डब्ल्यूएचओ ने आगे कहा, हम इसके नियंत्रण के लिए सिस्टम स्थापित करना चुनेंगे। और विश्व स्तर पर एमपॉक्स को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। या हम इससे घबरा जाएंगे, आने वाले समय में हमें इसे लेकर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये हम पर निर्भर करता है।

कैसे होते हैं लक्षण?

डब्ल्यूएचओ ने आगे कहा, यूरोप और दुनिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित होगी। एमपॉक्स (monkeypox symptoms), एक वायरल संक्रमण है, जो मवाद से भरे घावों का कारण बनता है। इसमें फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, जो आमतौर पर हल्के होते हैं लेकिन जान ले सकते हैं।

एमपॉक्स (monkeypox virus india) की क्लैड 1बी किस्म ने वैश्विक स्तर पर तबाही मचा दी है, यह नियमित रूप से अधिक आसानी से फैलता है। पिछले सप्ताह इस वैरिएंट के एक मामले की पुष्टि हुई थी एमपॉक्स का प्रसार स्वीडन और अफ्रीका में ज्यादा है।

हर महीने सामने आए 100 से ज्यादा मामले

क्लूज ने कहा कि इस वक्त हमारा फोकस नए क्लैड 1 स्ट्रेन पर है, यूरोप को कम गंभीर क्लैड 2 पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। इसको लेकर बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह और निगरानी सहित विविधता पर जोर दिया गया है। बता दें कि क्लूज ने कहा, क्लैड 2 एमपॉक्स स्ट्रेन के यूरोपीय क्षेत्र में हर महीने अब करीब 100 नए मामले सामने आ रहे हैं।

मणिपुर हिंसा में कारगिल योद्धा की पत्नी को नग्न अवस्था में परेड कराई गई और उनका रेप किया गया था- प्रियंका कक्कड़

सुषमा रानी

नईदिल्ली। मणिपुरहिंसा मामले में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को एक सनसनीखेज खुलासा किया। ''आप'' ने यह खुलासा मणिपुर दंगा मामले में न्यायिक आयोग को शपथ पत्र के साथ सौंपे गए एक ऑडियो टेप के माध्यम से किया है। इसमें दो आवाजें हैं। जिसमें एक केंद्रीय गृहमंत्री आमित शाह और दूसरी सीएम एन. बीरेन की बताई जा रही हैं। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस ऑडियो टेप का हवाला देते हुए कहा कि मणिपुर को एक साजिश के तहत जलाया गया। इसीलिए एक साल से जल रहे मणिपुर के सीएमएन. बीरेन को पद से नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीएम बीरेन को कह रहे हैं कि बम नहीं मारना है।

वहीं, सीएम बीरेन अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि बम चुपके से मारना है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मणिपुर में कारगिल योद्धा की पत्नी को नग्न अवस्था में परेड कराई गई थी और उनका रेप किया गया था। इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं कि भीड़ ने इन महिलाओं को कपड़े पहनाकर घर भेजा था। साथ ही यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि इसका क्या सबूत हैं कि इन महिलाओं का रेप हुआ है?

मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर ''आप'' की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि 3 मई 2023 को मणिपुर में दंगे शुरू हुए थे। तब से लेकर आज तक वहां हजारों घर जल चुके हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं, और कई महिलाओं का बलात्कार हुआ है। एक साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मणिपुर की डबल इंजन की सरकार अब तक दो समुदायों के बीच हिंसा को रोकने में विफल रही है। जब मणिपुर की स्थिति संभालने में असफल रहे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग उठने लगी, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। इसलिए उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। सवाल यह है कि यह किस तरह का सहयोग था? उन्हें अब तक क्यों नहीं हटाया गया। इसका जवाब अब उन टेप्स में सामने आ रहा है जो न्यायिक आयोग के समक्ष एक शपथ पत्र के साथ रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि इन टेप्स में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की आवाज है।

प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान टेप प्ले कर मीडिया को सुनाया। इसमें सीएम एन बीरेन सिंह हंसते हुए बता रहे हैं कि अमित शाह ने उनसे कहा कि 'अरे! बीरेन तुम बम मारते हो, नहीं मारना है,' जबकि बीरेन सिंह ने कहा कि चुपके से इस्तेमाल करेंगे। दो समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के बजाय मुख्यमंत्री चुपके से बम मारने के निर्देश दे रहे हैं। क्या यही वजह है कि मणिपुर में अब तक शांति कायम नहीं हो पाई है? प्रधानमंत्री अब तक एक बार भी मणिपुर नहीं गए। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के समय भी भाजपा के मुख्य प्रचारक मणिपुर नहीं पहुंचे। क्या अमित शाह सदन में इसी सहयोग की बात कर रहे थे, जिस कारण एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया?

प्रियंका कक्कड़ ने आगे कहा कि मणिपुर का सच तब सामने आया जब एक कारगिल के शहीद की विधवा को नग्न अवस्था में घुमाया गया। बाद में उसका बलात्कार और अत्याचार किया गया। उन महिलाओं ने इस घटना पर पूरा बयान दिया है। इसके बाद प्रियंका कक्कड़ ने दूसरा ऑडियो टेप प्ले किया जिसमें मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यह कह रहे हैं कि जिस भीड़ ने उन महिलाओं को नग्न करके घुमाया और फिर उनका बलात्कार किया, हमें यह कहना चाहिए था कि उस भीड़ ने उल्टा उन्हें कपड़े पहनाकर घर भेज दिया। इस बात का क्या सबूत है कि उनका बलात्कार भी हुआ है? यह मणिपुर की डबल इंजन सरकार का असली चेहरा है। क्या इनमें बेटियों और महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई संवेदना बची है?

प्रियंका कक्कड़ ने आगे कहा कि इसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगे केस को वापस लेने का आदेश पारित किया था। भाजपा सरकार कठुआ में बलात्कार के आरोपियों और बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हो गई थी। भाजपा ने प्रज्वल रेवन्ना को टिकट दिया और मोदी जी ने खुद उनके लिए वोट मांगे। भाजपा के बाहरी अध्यक्ष बलेश ढंकर, जिसे सदी का सबसे घटिया बलात्कारी कहा गया, ये सब लोग भाजपा से ही क्यों जुड़े हुए हैं? इन्हें यह ताकत कहां से मिलती है? जब इन्हें ऊपर से संरक्षण मिलेगा, तो क्या इससे उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? मणिपुर मामले में लगातार चौकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जवाब देना चाहिए कि अब तक एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया है? भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है?

दिल्ली में बारिश से आफत: सड़कें बनीं दरिया, जगह-जगह लगा जाम

दिल्ली में आज सुबह से ही आकाश में बादल छाए रहे। जिसके बाद कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश भी देखी गई। वर्षा के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। स्कूल और दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले सोमवार को रक्षाबंधन के दिन उमस ने लोगों का हाल बेहाल किया। देखिए जलभराव और ट्रैफिक जाम की तस्वीर।

नई दिल्ली। राजधानी में मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई। जिसके कुछ समय बाद ही सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस खबर के माध्यम से तस्वीरों में देखिए दिल्ली का हाल। कहीं ट्रैफिक जाम से घंटों सड़कों पर लोग फंसे रहे तो कहीं जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बनी।

पूर्वी दिल्ली : दिल्ली सरकार के शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद अस्पताल में वर्षा से हुआ जलभराव। पीडब्ल्यूडी के नाले जाम है, सड़क पर बने नाले में अस्पता में भरा वर्षा का पानी जा नहीं पा रहा है। डॉक्टरों की अस्पताल में हड़ताल है।

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास मुख्य मार्ग पर वर्षा से हुआ जलभराव।

किराड़ी के 70 फुटा रोड पर भरा पानी।

पटपड़गंज रोड पर गणेश नगर के पास अंडरपास में हुआ जलभराव।

जीटी करनाल रोड पर जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे जमा वर्ष का पानी।

एनएच -नौ की सर्विस रोड पर विनोद नगर के पास हुआ जल भराव।

शास्त्री पार्क में जलभराव से एक किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है।

पटपड़गंज रोड पर गणेश नगर के पास सड़क पर है जलभराव व फुटपाथ पर अतिक्रमण ऐसे में लोगों को चलने में समस्या आती है।

वर्षा के कारण एनएच-9 पर लगा जाम।

वर्षा से हुए जल भराव के कारण जीटी करनाल रोड व बाहरी रिंग रोड पर लगा यातायात जाम।

भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आधुनिक भारत के शिल्कार, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यालय में राजीव की तस्वीर पर पुष्पाजंलि अर्पित की। देवेन्द्र यादव ने राजीव भवन में राजीव गांधी के स्टेच्यु पर माल्यापर्ण भी किया।

देवेन्द्र यादव ने आज प्रातः राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर प्रार्थना करने के बाद राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजीव गांधी को याद किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजीव गांधी का देश सदैव ऋणी रहेगा।

उन्होंने राजीव गांधी के जन्मदिवस पर युवा उत्थान को संकल्पित प्रधान महेन्द्र यादव छात्रवृति योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें शिक्षा के अलग-अलग के क्षेत्र में प्रख्यात मेधावी छात्रों को छात्रवति देने के साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के अलावा वरिष्ठ नेता मनीष चतरथ, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, विधायक जय किशन, अमरीश गौतम, वीर सिंह धींगान, आसिफ मौहम्मद खान, वरिष्ठ नेता चतर सिंह, जतिन शर्मा, जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, मनोज यादव, सतबीर शर्मा, धर्मपाल चंदेला, जुबैर अहमद, इन्द्रजीत सिंह, सेवादल मुख्य संगठक सुनील कुमार, पूर्व पार्षद ईश्वर बागड़ी, राजेन्द्र तंवर, जे.पी. पंवार, अब्दुल हानन, पी.के. मिश्रा, राहुल शर्मा, संजय नीरज, अशोक भसीन, अजय अरोड़ा राजीव कौशिक, अब्दुल वाहिद कुरेशी, दीपक वशिष्ठ, त्रिलोक चौधरी, कमलेश चौहान, निकिता चर्तुवेदी और नीतू शर्मा मुख्य रुप से मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि राजीव एक दूरदर्शी एवं विचारशील व्यक्ति थे, जिन्होंने 21वीं सदी में देश के सामने आई चुनौतियां और जरुरतां का सामना करते हुए भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि राजीव की ही दूरदर्शिता थी जिसने कम्प्यूटर और दूरसंचार क्रांति को समय से पहले देश में लाए, जिसका परिणाम आज भारत तकनीकी क्षेत्र में दुनिया के देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है। यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवा को भागीदार बनाने के लिए राजीव ने उन्हें 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि राजीव के प्रधानमंत्रीत्व में असंख्य देशवासियों को रोजगार के नए अवसर मिले, गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए काम किया।

उन्होने कहा कि आज बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, गरीब, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर बढ़ते अत्याचार, संविधान के प्रारुप को बदलना, भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण कुछ ऐसे दंश है जिसे आज पूरा देश झेल रहा है, जिसकी राजीव गांधी ने कभी परिकल्पना भी नही की थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश की प्रगतिशीलता को रुकने नही दिया। नेहरु के प्रभावशाली नेतृत्व, इंदिरा और राजीव के बलिदान के बाद भी कदम दर कदम देश आगे बढ़ता चला गया है। शिक्षा के महत्व को हर देशवासी को बताने और विदेश नीति को व्यवस्थित बनाया, जिससे युवाओं को विदेशों में रोजगार मिलने की शुरुआत हुई।

वजीरपुर हादसे की जगह नाले को ढकना और 50 कदम दूर नाला खुला, सरकार का जनता को धोखा: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में सरकारों के भ्रष्टाचार के संक्रमण इतना अधिक फैल गया है कि हर बारिश के बाद दिल्ली डूब रही है। जलभराव में डूबकर मरते लोगों की दिल्ली सरकार को कोई चिंता नही है जबकि आज की बारिश के बाद जलभराव से नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को ट्रेफिक एडवाईज़री तक जारी करनी पड़ी।

उन्होंने आज वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के खुले नाले गिरने से 7 वर्षीय प्रिंस की मौत के बाद उसके परिवारजनों से मिलने गए। परिवार वालों ने नाला खुला होने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया जबकि पुलिस जो भी हादसे के लिए जिम्मेदार होगा उस पर कार्यवाही करेगी। यादव ने प्रिंस के परिवारजनों को 1 करोड़ मुआवजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जहां हादसा हुआ है, वहां तो नाले का ढक दिया गया है, परंतु 50 कदम दूर अभी भी नाला खुला हुआ है। इस मौके पर देवेन्द्र यादव के साथ पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता और अनिल भारद्वाज भी मौजूद थे।

उन्होने कहा कि प्रिंस की मौत के हादसे के साथ दिल्ली में जल भराव, नाले में डूबकर मरने वालों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। दिल्ली में हो रहे हादसे सरकार की लापरवाही के कारण हो रहे है। अगर दिल्ली सरकार अथवा निगम ने नालों को ढक दिया होता तो हादसा नही होता। खुले नाले का यह पहला हादसा नही दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी नालें में डूबने से लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने चिंता व्यक्त की कि मिंटो रोड़, कमला मार्केट, आईटीओ, बहादुरशाह जफर रोड़, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, पटेल चौक, आश्रम, आउटर सर्किल, गीता कॉलोंनी, नांगलोई, टीकरी बॉर्डर, बहादुर गढ़, पीरागढ़ी, झरोदा, नजफगढ़ पर जल भराव के कारण ट्रेफिक को डाइवर्ट करना पड़ा, यह दिल्ली की सरकारों की विफलता को उजागर कर रहा है कि केजरीवाल की दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने हजारों करोड़ गाद निकालने के नाम पर खर्च करके कोरा भ्रष्टाचार किया है। मानसून के आखिरी पड़ाव की बारिश के बाद पूरी दिल्ली डूब गई।

उन्होने कहा कि दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, मंत्री, दिल्ली की मेयर ने 9 जून को मानसून की पहली बारिश के बाद यह वादा किया था कि दिल्ली में जल भराव रोकने के इंतजाम किए जाएंगे परंतु हर बारिश में जल भराव ने प्रलय का रुप धारण किया और जल भराव, बेसमेंट में डूबने, नालों में डूबने, जल में करंट उतरने से, इमारते के नीचे दबने से मरना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम जल भराव से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आतिशी ने दावा करती हैं कि सरकार ने सभी नाले साफ कर दिए है और दूसरी तरफ सभी विधानसभाओं में उपर बहते सीवर के कारण पैदा हो रहे स्वास्थ्य संकट रोकने लिए अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और बहते सीवर के लिए मुख्य सचिव को दोषी ठहरा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल खुद मानते है कि यदि नालों की बेहतर तरीके से सफाई होती तो लोगों की जान नही जाती। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो अपने नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ती है। आखिर आतिशी सरकार की हर जिम्मेदारी को दूसरों का काम बताकर दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहती है, जबकि हर बारिश में दिल्ली डूब रही है।

'कुछ ही घंटों में विस्फोटक फट जाएगा', दिल्ली में कई बड़े मॉल और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल सहित कई अस्पतालों और मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं ई-मेल देखने के बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस को मौके से कुछ नहीं मिला है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के बाद कई बड़े मॉल और मैक्स सहित कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मैक्स हॉस्पिटल में मंगलवार सुबह 5 बजे ई-मेल पर धमकी दी गई। वहीं, स्टाफ ने 10 बजे के आसपास मेल देखा तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

जानकारी मिलने के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड पहुंची। बेसमेंट और ओपीडी एरिया में जांच-पड़ताल की। फिलहाल कहीं कुछ नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ई-मेल पर दिल्ली के दो-तीन अस्पतालों के साथ ही देश के 150 से अधिक अस्पतालों को धमकी दी गई है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि नांगलोई के एक अस्पताल में दोपहर 1.04 बजे और मध्य दिल्ली के चाणक्य पुरी स्थित प्राइमस अस्पताल से दोपहर 1.07 बजे कॉल आई, जिसमें बताया गया कि उन्हें बम की धमकी मिली है। अधिकारी ने बताया कि दमकल की गाड़ियां, बम का पता लगाने वाली टीमें और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गहन जांच की जा रही है।

इन मॉल को मिली धमकी

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई शॉपिंग मॉल को बम की धमकी भरा ई-मेल मिला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, चाणक्य मॉल, सेलेक्ट सिटीवॉक, एंबियंस मॉल, डीएलएफ, सिने पोलिस, पैसिफिक मॉल, प्राइमस हॉस्पिटल और यूनिटी ग्रुप को धमकी भरा ई-मेल मिला, जिसमें कहा गया था, ₹कुछ ही घंटों में विस्फोटक फट जाएगा।₹

मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां

दिल्ली पुलिस ने बताया कि जैसे ही मेल संज्ञान में आया, मॉल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। दिल्ली पुलिस ने सूचना मिलने के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी। बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। अभी तक कोई बम नहीं मिला है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि धमकी भरे ई-मेल भेजने में एक ही पैटर्न अपनाया गया है, जिसमें डेटलाइन का उल्लेख नहीं किया गया है। यह मेल कई मॉल और अन्य जगहों पर भेजा गया है। फिलहाल जांच चल रही है।

बताया गया कि आगे की जांच चल रही है। मामले में और जानकारी का इंतजार है। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को गुरुग्राम के एंबियंस मॉल में बम की धमकी मिली थी, लेकिन तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली।

दिल्ली सरकार के विभागो,निगमों,बोर्ड में भ्रष्ट,नाकारा कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी शुरू

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

दिल्ली सरकार के विभागो, निगमों, बोर्डो में भ्रष्ट,खराब परफामेंस, निकम्मे, कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रकिया पर अमल किया जाने वाला है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें एडहॉक, दानिक्स, इंस्पेक्टरो,दास, स्टेनो कैडर ग्रुप सी के कर्मचारी शामिल है। सूत्रो के मुताबिक दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग,ने सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी के बाद सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों,प्रधान सचिव,सचिव व विभागाध्यक्ष को आदेश जारी किए है। सूत्रो के मुताबिक दिल्ली सरकार में करीब 80 हजार अधिकारी व कर्मचारी,कार्यरत है।

इन कर्मचारियों के लिए हर महीने करीब 900 करोड रूपये वेतन के मद में जारी किए जाते है। एक सीनियर अफसर के हवाले से पता चला है कि ऐसे भ्रष्ट, और

नाकारा कर्मियों के खिलाफ एफआर-56(जे)रूल्स के तहत कार्रवाई की तैयारी है। जबरन रिटायर की कार्रवाई 50 साल से अधिक उम्र के भ्रष्ट व नाकारा कर्मचारियों पर की जा रही है। दरअसल ये अभी साफ नही है कि 50 साल से ऊपर की आयु के कितनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। सरकार की ऐसी मंशा और आदेश के बाद दिल्ली सरकार के सभी विभागो में अफरा-तफरी का माहौल है। हर डिपार्टमेंट में इस बात की चर्चा है, कि इसमें किसका नंबर आता है? इसके लिए बाकायदा विभाग प्रमुख स्तर पर कमेटियां बनाई जाएगी।इन कमेटियों को अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट तैयार कर भेजनी होगी। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर विशेष नजर है।जिनके खिलाफ विजिलेंस,दिल्ली पुलिस या अन्य विभाग में मुकदमें दर्ज है।सभी विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट पहले मुख्य सचिव को सौपेगे। उसके बाद प्रधान सचिव नरेश कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसे अधिकारियो व कर्मचारियों की सूची उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास फाइल मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। एलजी हाऊस से मंजूरी मिलते ही ऐसे लोगो को सरकारी सेवा से छुटकारा दे दिया जाएगा।

एमसीडी का हिंदूराव अस्पताल बारिश से बदहाल

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। राजधानी दिल्ली को लंदन बनाने वाले खुद तो जेल में बैठे है, पर दिल्ली के लोग कभी,पानी, कभी बारिश के जलभराव तो कभी बिजली की मार झेलने को मजबूर है। मंगलवार को दिल्ली में हुई बारिश ने राजधानी दिल्ली के चक्के जाम कर दिए। मिनटों रोड अंडर पास, इन्द्रलोक, मधुबन चौंक अंडरपास से लेकर क्नॉट प्लेस तक पानी में समां गया। सुबह सवेरे हुई तेज बरसात का आलम ये था कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चो की गाडी, एंबुलेंस में फंसे मरीज ,दफ्तर को जाने वाले लोग, स्कूल टीचर्स से लेकर अस्पताल तक जलभराव की जद में आ गए। दिल्ली के सबसे व्यस्तम हिंदूराव अस्पताल तक के वार्डो में बारिश के पानी ने जगह बना ली। मरीज हैरान और परेशान दिखाई दिए। हिंदूराव अस्पताल के वार्ड 3 की बदहाली में कथित लंदन का नजारा दिखाई दिया। इस अस्पताल में खंडहर होती इमारत से झडता पलस्तर, उखडे सरिये, गिरते झज्जे,गंदगी की भरमार वाली आए दिन टीवी की खबर बनती रहती है। हर बार निगम की मेयर,समेत निगम प्रशासन बडी-बडी बाते और दावों में इस अस्पताल की तमाम हालात को सुधारने के दावे जरूर करते है पर यहां के परिसर में घुसते ही मरीजों को मुंह पर कपडा ढक कर चलना पडता है। बहरहाल महीने से दिल्ली में बरसात ने अपनी दस्तक दे रखी है बावजूद इसके निगम के अधिकारी से लेकर कर्मचारियों ने तक आराम फरमा रहे हैं।ना काम करने की कसम खाई है। नालों की भरी गाय, सीवर जाम, और अस्पताल का बुरा हाल, जलभराव ,गंदा पीने का पानी ये सब कहानी है राजधानी की। व्यवस्था और राजनीति को बदलने वाले लगता है खुद ही बदल गए है तभी तो राजधानी दिल्ली की सूरते हाल बद बदतर हो गई है।

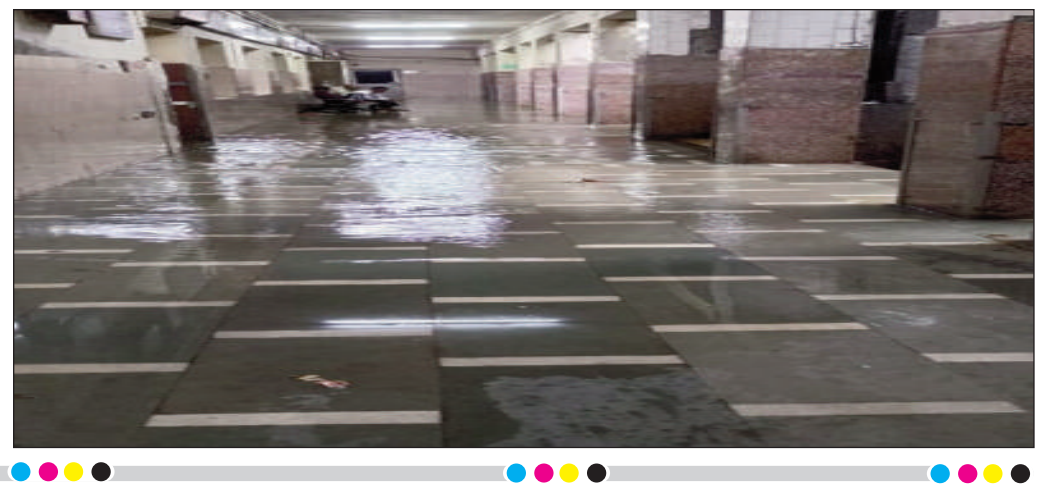

गुरुग्राम में झुग्गी माफिया फिर बसा रहे अवैध शहर, दो महीने पहले हुई थी कार्रवाई

पिछले साल अगस्त में नूंह ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा होने पर शहर के कई इलाकों में बसी झुग्गियां बिलकुल खत्म हो गई थीं। यहां बसें लोग चले गए थे लेकिन एक बार फिर झुग्गी माफिया के सक्रिय होने से अवैध बसावट फिर से हो गई है। दो महीने पहले ही कई इलाकों में पुलिस ने अवैध रूप से झुग्गी बसाने पर कार्रवाई की थी।

गुरुग्राम। एक बार फिर झुग्गी माफिया पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे गुरुग्राम शहर में अवैध रूप से झुग्गियां बसा रहे हैं। थाना पुलिस कई बार अवैध झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई करती तो है, लेकिन यह शायद दिखावे की होती है। अगर सही मायने में कार्रवाई होती और निरंतर नजर रखी जाती तो दोबारा झुग्गियां नहीं बसतीं।

पुलिस-प्रशासन बेपरवाह

शहर के पाश इलाकों में बनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों के पास सैकड़ों झुग्गियां देखी जा सकती हैं, लेकिन शायद पुलिस-प्रशासन की इस ओर नजर नहीं जाती। चाहे वह तिगरा गांव हो या फिर नखड़ौला का इलाका।

सेक्टर 37 का सीही गांव हो या फिर सिलोखरा के पास की जगह। सभी जगहों पर झुग्गियां बसी हुई हैं और अवैध रूप से लोग यहां रह रहे हैं।

आपराधिक गतिविधियों को देते हैं अंजाम

राजेंद्रा पार्क, सेक्टर 56, सेक्टर 65 समेत अन्य थाना पुलिस ने झुग्गियों को हटाकर कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया था। झुग्गी माफिया सस्ते दामों पर लोगों को किराये में झुग्गियां दे देते हैं। इनमें बंगाल, बिहार, असम, समेत अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों के लोग अवैध रूप से रह रहे हैं।

इनका न तो वेरिफिकेशन होता है और न ही इनके पास कोई लीगल डाक्यूमेंट। यहां फर्जीवाड़े से कई लोग आधार कार्ड बनवाकर छोटी-मोटी रेहड़ियां लगाते हैं तो कई लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

शहर के लोगों की सुरक्षा के प्रति गुरुग्राम पुलिस प्रतिबद्ध है। झुग्गियों को लेकर पहले भी समय-समय पर कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में अभियान चलाने के निर्देश दिए जाएंगे। - विकास अरोड़ा, पुलिस आयुक्त

यहां बसाई गई हैं अवैध झुग्गियां

गुरुग्राम शहर के सेक्टर 70, नखड़ौला, नाथूपुर, सिलोखरा, मानेसर, बादशाहपुर, सिकंदरपुर, सेक्टर 56, सेक्टर 37, तिगरा, वजीराबाद समेत अन्य जगहों पर झुग्गियां बसाई गई हैं।

नोएडावासियों को उमस से मिली राहत, जलभराव और जाम से लोग हो रहे परेशान

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा के लोगों को मंगलवार की सुबह झमाझम बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली। लेकिन स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को जलभराव और ट्रैफिक जाम के कारण घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। सेक्टर 16 18 और 62 सहित फ्लाई-ओवर पर कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया। लोगों ने प्रशासन को सही इंतजाम ना करने के आरोप लगाए।

नोएडा। औद्योगिक नगरी में मंगलवार सुबह हुई मूसलाधार वर्षा के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में भारी जलभराव हो गया। जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सुबह के समय आफिस, कंपनी, फैक्ट्री, स्कूल, कालेज जाने वाले लोगों को जाम और पानी से भरी सड़कों से गुजरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

चौराहों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक की स्थिति बदतर

सेक्टर-18, सेक्टर 62, और डीएनडी फ्लाईवे सहित कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को कई घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। डीएनडी फ्लाईवे पर वाहनों की रफ्तार कम होने से लंबा जाम लग गया। सेक्टर-12/22 और सेक्टर 58 के चौराहों पर भी पानी भर जाने से ट्रैफिक की स्थिति बदतर हो गई।

जाम में फंसे लोगों का कहना है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा जल निकासी व्यवस्था को ठीक से न बनाए रखने के कारण हर बार तेज वर्षा के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इस बार वर्षा के कारण कार्यालय और स्कूल जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

लोगों ने वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन से की शिकायत

नोएडा प्राधिकरण दावा है कि जलभराव की समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि वर्षा की रफ्तार के कारण स्थिति को तुरंत सुधारना संभव नहीं हो पाया। कई इलाकों में लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा करते हुए प्रशासन से शिकायत की है।

प्राधिकरण के अधिकारी इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल नागरिकों को जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि सुबह के समय तेज हवा संग वर्षा के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अधिकतम तापमान में भी कमी आई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बरसात के मौसम में कैसे काबू में आया डेंगू का प्रकोप? इन लक्षणों से होती है बीमारी की पहचान

परिवहन विशेष न्यूज

मंगलवार को विश्व मच्छर दिवस रहा। वहीं लोगों की जागरूकता से मच्छरों का प्रकोप कम हुआ है। हालांकि बरसात के मौसम में ये पनपने लगते हैं। इस साल मच्छरों के काटने से होने वाले डेंगू के मामले काफी हद तक काबू में है। इ पढ़िए आखिर डेंगू के क्या-क्या लक्षण होते हैं।

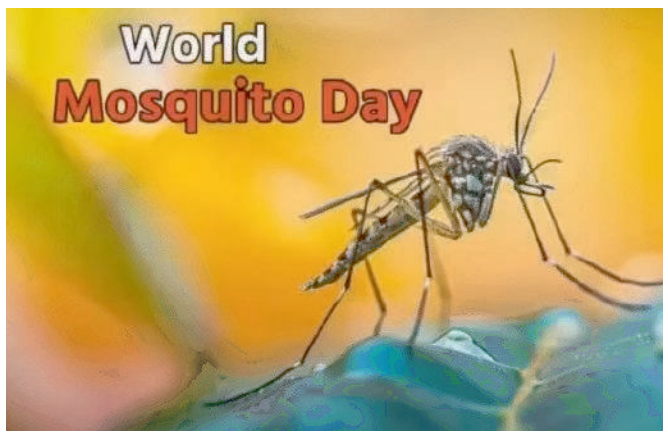

गाजियाबाद। आज विश्व मच्छर दिवस है, जिसका मकसद लोगों को मच्छर के काटने होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। मच्छर के काटने से होने वाले डेंगू का प्रकोप इस बार की बरसात में किसी हद तक काबू में है।

इसके पीछे संचारी रोग अभियान के तहत लोगों में जागरूकता और मौसम का मिजाज भी अनुकूल रहा। लगातार रिमझिम वर्षा होने पर पानी एकत्र हो जाता है और वह सूख नहीं पाता है। ऐसे में मच्छरों का लार्वा उसमें पनप जाते हैं। गत वर्ष डेंगू के इन दिनों तक जहां 50 से अधिक केस सामने आए थे।

वहीं, इस बार यह घटकर छह रह गए, लेकिन मलेरिया गत वर्ष के मुकाबला जस का तस है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अभियान के तहत इकट्ठा हुए पानी में जांच के दौरान अगस्त माह में 450 डेंगू लार्वा मिला है। बरसात के दिनों में मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है।

इस मौसम में मच्छर के काटने से कई बीमारियां पनपती हैं। इनमें डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस और चिकनगुनिया शामिल हैं। खासकर, डेंगू और मलेरिया से अधिक बचाव जरूरी है। जुलाई में 683 और अगस्त माह में 450 स्थानों पर डेंगू लार्वा एयर कूलर, गमलों अन्य पात्रों में मिला।

वहीं, जिला मलेरिया विभाग की ओर से एंटी लार्वा का छिड़काव कराकर लार्वा को नष्ट किया गया। 16 से 30 जुलाई के बीच 8.32 लाख घरों का संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत सर्वे किया गया, जिसमें 457 बुखार के मरीज, 17 क्षय रोगी की पहचान हुई। इनका स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उपचार कराया गया।

डेंगू रोग के लक्षण

- बुखार व सिर में अचानक तेज दर्द
- मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द
- उल्टी और जी मिचलाना
- आंखों के पीछे दर्द होना
- गंभीर स्थिति में नाक, मुंह और मसूड़ों से खून आना
- बार-बार बुखार आना

डेंगू लार्वा के संवेदनशील क्षेत्र

नासिरपुर फाटक और महेंद्रा एंक्लेव, झंडापुर, करहेड़ा, कनावनी, अर्थला, नंदग्राम, नूरनगर सिहानी, पीला क्वार्टर, प्रताप विहार सेक्टरा-11, सिद्धार्थ विहार-दो, राहुलविहार, डूंडाहेड़ा, बागू, क्रिश्चियन नगर, मिर्जापुर, कैला भट्ठा, दीनदयालुपरी, सेवानगर, मालीवाड़ा, गगन विहार, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, लोहिया नगर, सर्वोदय नगर, सुंदरपुरी, ऊदलनगर, दौलतपुरा समेत 27 क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से संवेदनशील घोषित किए गए हैं।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान का असर दिखाई दिया है। लोगों में डेंगू, मलेरिया से बचाव को लेकर लोगों में जागरूकता के साथ इस बार मौसम ने भी साथ दिया है। गत वर्ष के मुकाबले इस बार डेंगू के केस 50 के मुकाबले छह और मलेरिया के गत वर्ष की तरह आठ केस मिले हैं। डेंगू फैलाने वाला मच्छर साफ इकट्ठा हुए पानी में पनपता है। यह मच्छर दिन के समय काटता है। बचाव के लिए शरीर पर पूरे कपड़े पहनें।

- डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा, जिला मलेरिया अधिकारी

गाजियाबाद में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, लगा भीषण जाम

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में मंगलवार सुबह हुई बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे कई सड़कों पर जाम लग रहा है। बारिश से सुबह समय से स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदिरापुरम के काला पत्थर रोड और मोहन नगर तिराहा पर जलभराव हो गया है। वहीं नोएडा सेक्टर 63 छिजारसी के पास एनएच-9 पर भी जाम लग रहा है।

साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र का सबसे बड़ा बृज विहार का नाला कूड़े से भरा हुआ है। मंगलवार सुबह डेढ़ घंटे बारिश के बाद जलभराव हो गया। जब लोग घर से बाहर निकले तो सड़कें जलमग्न नजर आईं। जीटी रोड पर अर्थला, मोहन नगर सहित कई जगह पर पानी भर गया।

इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र साइट चार में सौर ऊर्जा रोड पर पानी भर गया। कामगारों को फैक्ट्री पहुंचने पर परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांस हिंडन की राजेंद्र नगर, शालीमार गार्डन, भोपुरा, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी, श्याम पार्क, गरिमा गार्डन, करेहड़ा, इंदिरापुरम का शक्ति खंड, ज्ञान खंड, वैभव खंड, नीति खंड में जगह-जगह पानी भरा रहा। दिल्ली जाने वाले मार्ग पर नोएडा सेक्टर 63 छिजारसी के पास एनएच-9 पर लगे जाम में फंसे वाहन।

वसुंधरा फ्लाईओवर के पास सड़क पर जलभराव

एनएच नौ पर भी कई जगह पानी भर गया। वसुंधरा फ्लाईओवर के पास 600 मीटर सड़क पर जलभराव हो गया। यहां दो-दो फीट पानी भरने की वजह से यहां निकलने वाले कुछ वाहनों के इंजन में पानी चला गया। जिस वजह से वाहन वाहन बंद हो गए।

इंदिरापुरम के काला पत्थर रोड पर पानी भर गया। मोहन नगर तिराहा पर जलभराव हो गया। नगर निगम ने कई जगह पंप लगाकर पानी निकाला। लोग नगर नगर निगम को फोन कर शिकायत करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। जलभराव के कारण सुबह में जीटी रोड पर जाम लगा रहा।

वसुंधरा और हिंडन नहर रोड पर भी जाम

गाजियाबाद की ओर से दिल्ली जाने वाले वाहन हिंडन पुल से वसुंधरा की ओर मुड़ गए। ऐसे में वसुंधरा और हिंडन नहर रोड पर भी जाम लग गया। दिल्ली वजीराबाद रोड भोपुरा और गरिमा गार्डन में जाम लग गया। लिंक रोड पर वसुंधरा फ्लाईओवर के पास भी वाहनों की गति धीमी हो गई।

सौर ऊर्जा रोड पर सीईएल कंपनी और रोडवेज डिपो के पास पानी भरने से जाम लग गया। वहीं लोनी और खोड़ा में भी जलभराव से जाम की स्थिति बनी। नगर पालिका परिषद के अधिकारियों से लोगों ने शिकायत की।

विकसित भारत को गढ़ने के संकल्पों का उद्बोधन

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री मोदी के सम्बोधन को वास्तविकता की रोशनी में नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत के रूप में देखा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को जरूरी बताने के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफार्म्स तक, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों से लेकर गवर्नेस मॉडल, रोजगार, व्यापार, रक्षा, चिकित्सा समेत कई विषयों की चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लालकिले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस का अब तक का सबसे लम्बा 98 मिनट का 11वां राष्ट्रीय उद्बोधन एक विशाल एवं विराट इतिहास को समेटे हुए नये भारत के नये संकल्पों की बानगी है। जो आजादी के अमृतकाल को अमृतमय बनाने के लिये लोगों को ऊंचे सपने देखने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान की वैश्विक एवं राजनैतिक चुनौतियों को भविष्य की अपनी दृष्टि पर हावी नहीं होने दिया। यह उद्बोधन भारत की भावी दशा-दिशा रेखांकित करते हुए उसे विश्व गुरु बनाने एवं दुनिया की आर्थिक महाताकत बनाने का आह्वान है। यह शांति का उजाला, समृद्धि का राजपथ, उजाले का भरोसा एवं महाशक्ति बनने का संकल्प है। लालकिले से जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो वह भारत के महान लोकतंत्र की उस आत्मा को साकार करता है जो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के भीतर बसती है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्बोधन को वास्तविकता की रोशनी में नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत के रूप में देखा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को जरूरी बताने के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफार्म्स तक, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों से लेकर गवर्नेस मॉडल, रोजगार, व्यापार, रक्षा, चिकित्सा समेत कई विषयों की चर्चा की। उन्होंने न्यायिक सुधारों पर आगे बढ़ने का भी संकेत दिया। इसके साथ ही वह विपक्ष को निशाना बनाने से नहीं चूके और सरकार का एजेंडा उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। निश्चित ही अब तक हुए लालकिले की प्राचीर के उद्बोधनों में सर्वाधिक प्रेरक, संकल्पमय एवं विकसित भारत की इबारत लिखने वाला यह उद्बोधन रहा। अंधेरों को चीर कर उजाला की ओर बढ़ते भारत की महान यात्रा के लिये सबके जागने, संकल्पित होने एवं आजादी के अमृतकाल काल को अमृतमय बनाने के लिये दृढ़ मनोबली महानायक का आह्वान है।

यह वीनर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है ! और कीमत बहुत सस्ती हैऔर जानें

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में खास एवं ऐतिहासिक होने की अनुगूंजें इस उद्बोधन में साफ सुनाई दी, जैसाकि उनके पूर्व के दो कार्यकाल इस लिहाज खास रहे हैं कि उनकी पार्टी के जिन लक्ष्यों को राजनीति की अन्य धाराएं लगभग नामुमकिन मानती थीं, उन्हें देश के एजेंडा का हिस्सा बनाते हुए हासिल कर लिया गया। चाहे वह अयोध्या में राममंदिर बनाने की बात हो या अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल विशेष दर्जा खत्म करने की। तीसरे कार्यकाल में ऐसा ही एक और लक्ष्य है कॉमन सिविल कोड जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना बाकी है। मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में इसका जिक्र करके यह संकेत दिया है कि इसे देशवासियों के लिए स्वीकार्य बनाना और लागू करना उनकी सरकार की प्राथमिकता में काफी ऊपर है। उनके शब्दों में मौजूदा सिविल कोड एक तरह से साम्प्रदायिक नागरिक संहिता है। देश को ऐसे सिविल कोड की जरूरत है, जिससे धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिले। जब देश में अधिकतर मामलों में नागरिकों पर एक समान कानून लागू होते हैं तो फिर अलग-अलग धर्मों के

अपने अलग-अलग लॉ भारत के संविधान पर सवालिया निशान लगाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी देश में बार-बार होने वाले चुनावों को विकास की राह में बाधा मानते हैं और यह कोशिश करते रहे हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने लगें। लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद उनकी पार्टी और सरकार का यह अजेंडा आगे बढ़ना मुश्किल भले ही माना जा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इसका भी जिक्र करते हुए यह संकेत दिया कि इस दिशा में उनकी सरकार के प्रयास जारी रहेंगे। इन सबके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की खास उपलब्धियों और उसके सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र करना नहीं भूले।

अनेक विशेषताओं एवं विलक्षणताओं वाले इस बार के उद्बोधन एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा गया, उससे यही स्पष्ट हुआ कि वह अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बाद भी वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं हैं। इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने आंतरिक और बाहरी चुनौतियों की चर्चा करते समय बांग्लादेश के हालात का भी जिक्र किया और वहां के हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक ओर जहां जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार किया, वहीं दूसरी ओर कोलकाता की दिल दहलाने वाली घटना को ध्यान में रखते हुए नारी सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने यह कहकर देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन लाने की भी पहल की कि आने वाले समय में एक लाख ऐसे युवाओं को अपनी पसंद के राजनीतिक दलों में सक्रिय होना चाहिए, जिनके परिवार के लोग पहले कभी राजनीति में न रहे हों। निश्चित ही भारतीय राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति एवं नए विचारों और नई ऊर्जा से ओतप्रोत युवा नेताओं की आवश्यकता है।

यह ऐतिहासिक उद्बोधन कोरा राजनीतिक उद्बोधन न होकर राष्ट्रीयता को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने का सशक्त आह्वान है जो इस बात विश्लेषण करता है कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए। अंतरिक्ष हो या समंदर, धरती हो या आकाश, देश हो या दुनिया आज हर जगह भारत का परचम फहरा रहा है, भारत ने जितनी प्रगति की है उसे देखकर हर देशवासी को भारतीय होने का गर्व हो रहा है तो इसका श्रेय मोदी को दिया जाना कोई अतिश्योक्ति नहीं है, इसकी चर्चा करना राजनीतिक नहीं, भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समृद्धि का बखान है। हर भारतवासी मोदी के उद्बोधन से इसलिये भी प्रेरित एवं प्रभावित हुए है कि 'मिशन मोड' पर 'ईज ऑफ लिविंग' को पूरा करने के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए उसे आगे बढ़ा रहे है। उन्होंने व्यवस्थित मूल्यांकन, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की बहुत जरूरी बात कही है। उन्होंने भारत में जीवन को आसान बनाने की अपेक्षा की, ताकि अमीरों एवं युवा प्रतिभाओं के पलायन को रोका जा सके। मोदी ने देश की जनता में जोश एवं संकल्प जगाते हुए ऐसा ही कुछ कहा जो जीवन की अपेक्षा को न केवल उद्घाटित करता है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को परत-दर-परत खोलकर रख देते हैं।

'विकसित भारत' की थीम के साथ इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस उद्बोधन भारत की भावी दशा-दिशा को रेखांकित करते हुए कह रहा है कि देश किन्हीं समस्याओं पर थमे नहीं, रूके नहीं, क्योंकि समाधान तलाशते हुए आगे बढ़ना ही जीवंत एवं विकसित देश की पहचान होती है। इसके लिये जो अतीत के उत्तराधिकारी और भविष्य के उत्तरदायी है, उनको दृढ़ मनोबल और नेतृत्व का परिचय देना होगा, पद, पार्टी, पक्ष, प्रतिष्ठा एवं पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर। यही भावना सबल सक्षम और समरस राष्ट्र बनाएगी और विश्व में भारत का मान बढ़ाएगी, इसी से भारत विश्वगुरु बनेगा। हम भारत के लोग विश्व मंगल की कामना की पूर्ति तभी अच्छे से कर सकते हैं जब पहले राष्ट्र मंगल की भावना से ओतप्रोत हों। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने पिछले 78 वर्षों में जो प्रगति की उडान अपनी विविधता को संजाये हुए भरी है उससे पूरी दुनिया हैरत में है। बड़े-बड़े देश अब भारत के लोगों के विकास, ज्ञान और उनकी मेहनत के दीवाने हैं। दुनिया के हर कोने में भारतीय अपना झंडा गाड़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के खिलाफ लड़ने का आह्वान भी किया क्योंकि ये गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों का हक छीनते हैं। उन्होंने नवाचार के इच्छुक उद्यमियों को विशेष रूप से संबोधित किया गया। भारत का निर्यात बढ़ना जरूरी है और इसके लिए ऐसे उत्पाद बनाने की जरूरत है, जिनकी विश्व स्तर पर मांग हो। देश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के मकसद से अगले पांच वर्षों में 75000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की घोषणा महत्वपूर्ण है। ऐसी ही घोषणाओं से भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

नगर परिषद ने ई-रिक्शाओं पर नंबर लगाना भूली, 3 हजार में से 1 हजार का ही नंबर लगाया, रूट चार्ट भी नहीं बना

परिवहन विशेष न्यूज

किशनगंज में ई-रिक्शा परिचालन और इससे होने वाली जाम की समस्या पर नियंत्रण के प्रति नगर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। शहर में तीन हजार से अधिक ई-रिक्शा संचालित हैं। इनमें से एक तिहाई ई-रिक्शा बंगाल से आते हैं। शहर में एक भी पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण ई-रिक्शा चौराहों पर खड़े होकर यात्रियों का इंतजार करते हैं। इससे रोजाना जाम की स्थिति बनती है। इसे नियंत्रित करने के लिए नगर प्रशासन की ओर से मास्टर प्लान बनाया गया था। लेकिन यह अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया।

नगर परिषद को शहर में चलने वाले सभी ई-रिक्शा को नंबर देना था और उनका रूट चार्ट निर्धारित करना था। ई-रिक्शा की नंबरिंग भी शुरू कर दी गई। करीब तीन दिनों तक नगर निगम कर्मियों ने टाउन हॉल के सामने कैंप लगाकर नंबरिंग का काम किया। जिसमें करीब एक हजार ई-रिक्शा की नंबरिंग की गई। इसके बाद नगर परिषद शेष ई-रिक्शा की नंबरिंग करना भूल गई। न तो ई-रिक्शा की नंबरिंग का काम पूरा हुआ और न ही रूट चार्ट निर्धारित हो सका।

हुंडई अलकाजर फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में 9 सितंबर को मारेगी एंट्री, लॉन्च डेट हुई कनफर्म

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में 9 सितंबर 2024 को लॉन्च होने वाली है। यह थ्री-रो एसयूवी हुंडई क्रेटा पर आधारित है। केबिन में क्रेटा के साथ साझा किए गए नए लेआउट सहित अपग्रेड किए जाएंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दो 10.25-इंच स्क्रीन देखने की उम्मीद है। सबसे बड़ा अपडेट लेवल 2 ADAS का समावेश होगा।

नई दिल्ली। Hyundai Motor India ने अगले महीने आने वाली Alcazar facelift के लॉन्च की तारीख की पुष्टि कर दी है। हुंडई अल्काजर फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में 9 सितंबर, 2024 को लॉन्च होने वाली है। यह थ्री-रो एसयूवी हुंडई क्रेटा पर आधारित है। फेसलिफ्ट वर्जन में नए फीचर्स सहित मॉडल में व्यापक अपग्रेड किए जाएंगे। आइए, इसके बारे जान लेते हैं।

डिजाइन अपडेट

पिछली स्पाई शॉट्स में अल्काजर फेसलिफ्ट पर नई क्रेटा की तरह ही अपडेटेड फ्रंट डिजाइन का वादा किया गया है। अडेटेड ग्रिल और फ्रंट बंपर के साथ नए सिग्नेचर एलईडी डीआरएल डिजाइन देखने की उम्मीद है, जो मॉडल को और अधिक गोल रूप प्रदान करेगा। रियर प्रोफाइल में भी नए एलईडी टेललाइट्स और टेलगेट के साथ-साथ बंपर सहित बदलाव देखने को मिलेंगे। मॉडल को नया लुक देने के लिए नए अलॉय व्हील को छोड़कर प्रोफाइल में मामूली बदलाव किए जाएंगे।

फीचर्स और इंटीरियर

केबिन में क्रेटा के साथ साझा किए गए नए लेआउट सहित अपग्रेड किए जाएंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दो 10.25-इंच स्क्रीन देखने की उम्मीद है। तीन-पंक्ति वाली इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और भी बहुत कुछ मिलेगा। उम्मीद है कि हुंडई इंटीरियर को रिफ्रेश करने के लिए नए मटीरियल और अपहोल्स्ट्री ऑप्शन का इस्तेमाल करेगी। हालांकि, सबसे बड़ा अपडेट लेवल 2 ADAS का समावेश होगा।

इंजन और स्पेसिफिकेशन

अल्काजर फेसलिफ्ट में पेट्रोल और डीजल यूनिट के ही विकल्प मिलेंगे। मौजूदा मॉडल में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 158 bhp और 253 Nm का पावर देता है, जबकि 1.5-लीटर डीजल इंजन 114 bhp और 250 Nm का पावर देता है। पेट्रोल मोटर को 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT के साथ जोड़ा गया है, जबकि डीजल 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ उपलब्ध है। हुंडई ने पहले अल्काजर को 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ भी पेश किया था, जिसे 2023 में बंद कर दिया गया था।

मध्य प्रदेश सरकार की ईवी पॉलिसी से इंदौर उत्साहित, 31 हजार से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड

परिवहन विशेष न्यूज

राज्य सरकार की ईवी पॉलिसी से इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी। फिलहाल इंदौर में अब तक 31 हजार से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रदेश में किसी तरह की छूट न होने से ईवी वाहनों की बिक्री अपेक्षाकृत कम हो रही थी। अब प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी बनने जा रही है। इसमें सब्सिडी की घोषणा की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत अन्य राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इनकी खरीद पर सब्सिडी दे रहे हैं। इससे उन राज्यों में ईवी को बढ़ावा मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश कोई छूट न देकर पीछे रह गया। अब राज्य नई ईवी नीति बनाने जा रही है, जिसमें सब्सिडी की घोषणा होने की संभावना है।

इंदौर का ईवी बाजार और ऑटोमोबाइल उद्योग उत्साहित है। पीथमपुर और सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में ईवी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां काम कर रही हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि नई नीति के बाद इंदौर और पीथमपुर में नई ईवी उत्पादन इकाइयां स्थापित होंगी।

इंदौर में ईवी वाहनों की संख्या 31,000 के पार हो गई है। सड़कों पर 19,000 से ज्यादा ईवी दोपहिया वाहन दौड़ रहे हैं। कारों की बात करें तो इनकी संख्या भी 1,100 के पार हो गई है। ई-रिक्शा 8,000 के करीब हैं। ई-रिक्शा कारों की संख्या 1,525 है। थ्री-व्हीलर सवारियों की संख्या भी 547 के करीब पहुंच गई है। शहर में 70 ई-बसें भी चल रही हैं। मोटर कैब की संख्या भी 40 तक पहुंच गई है।

हुंडई एक्स्टर सीएनजी वर्सेज टाटा पंच सीएनजी फीचर, इंजन और कीमत में कौन बेहतर? खरीदने से पहले जान लीजिए

परिवहन विशेष न्यूज

Tata Punch और Hyundai Exter दोनों एसयूवी बॉडी स्टाइल के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। Hyundai Exter CNG की शुरुआती कीमत 8.50 लाख रुपये है जबकि SX और SX नाइट एडिशन की कीमत क्रमश: 9.23 लाख रुपये और 9.38 लाख रुपये है। दूसरी ओर टाटा पंच iCNG की शुरुआती कीमत 7.23 लाख रुपये है। वहीं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की कीमत 9.85 लाख रुपये है।

नई दिल्ली। Hyundai ने कुछ महीने पहले ही Exter Hy-CNG Duo को 8.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था। ट्विन सीएनजी सिलेंडर के साथ हाई-सीएनजी डुओ कॉन्फिगरेशन, सिंगल-सिलेंडर वेरिएंट के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करने के लिए बनाया गया है। S से लेकर SX नाइट एडिशन तक, हुंडई एक्सटर हाई-सीएनजी डुओ तकनीक के साथ उपलब्ध है। अपने सेगमेंट में ये Tata Punch iCNG को टक्कर देती है। आइए, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन और डायमेंशन

टाटा पंच और हुंडई एक्सटर, दोनों एसयूवी बॉडी स्टाइल के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। पंच अपने लार्ज फुटप्रिंट के साथ अधिक पारंपरिक एसयूवी रुख अपनाती है। लंबाई में 3,827 मिमी और चौड़ाई में 1,742 मिमी की माप के साथ, पंच एक्सटर की तुलना में सड़क पर बेहतरीन प्रजेंस प्रदान करती है।

हालांकि, वाहन की ऊंचाई के मामले में हुंडई एक्सटर पीछे है। टाटा पंच दिखने में लंबी होने के बावजूद, रूफ रेल को शामिल करते हुए एक्सटर वास्तव में 1,631 मिमी ऊंचा है, जो टाटा समकक्ष से अधिक है। इसके अतिरिक्त, व्हीलबेस के मामले में भी पंच के 2,445 मिमी की तुलना में 2,450 मिमी व्हीलबेस के साथ हुंडई एक्सटर आगे है।

इंजन और स्पेसिफिकेशन

हुंडई एक्सटर और टाटा पंच दोनों में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी पावरट्रेन है। एक्सटर में 1.2-लीटर, बाई-फ्यूल इंजन है, जो 68 बीएचपी और 95 एनएम का टॉर्क देता है। बाद वाले में भी 1.2 लीटर का बाई-फ्यूल पेट्रोल इंजन है, लेकिन 72 बीएचपी पर थोड़ा ज्यादा पावर आउटपुट के साथ, जबकि दूसरे की तरह ही 95 एनएम का टॉर्क फिगर पैदा करता है।

हुंडई एक्सटर हाई-सीएनजी डुओ के लिए क्लेम्ड माइलेज 27.1 किमी/किलोग्राम है, जबकि टाटा पंच आई-सीएनजी 26.99 किमी/किलोग्राम का दावा किया गया माइलेज देती है।

फीचर्स

हुंडई एक्सटर अपने 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एपल कारप्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, दो 12V पावर सॉकेट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और फास्ट-चार्जर टाइप-सी पोर्ट के साथ आती है। पंच में छह स्पीकर, रेन-सेंसिंग वाइपर, वॉयस-एक्टिवेटेड सनरूफ, फ्रंट आर्मरेस्ट और कई यूएसबी और टाइप-सी पोर्ट के साथ सात इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।

कीमत

Hyundai Exter CNG की शुरुआती कीमत 8.50 लाख रुपये है, जबकि SX और SX नाइट एडिशन की कीमत क्रमशः 9.23 लाख रुपये और 9.38 लाख रुपये है। दूसरी ओर, टाटा पंच iCNG की शुरुआती कीमत 7.23 लाख रुपये है। वहीं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की कीमत 9.85 लाख रुपये है। ये सभी कीमतें एक्स शोरूम हैं।

एमजी विंडसर ईवी को मिलेगा बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, नए टीजर में दिखी झलक, 11 सितंबर को होगी लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

Windsor EV का नया टीजर जारी किया है। टीजर से पता चलता है कि MG Windsor EV सिंगल-पैन फिक्स्ड ग्लास रूफ के साथ आएगी। इसका मतलब है कि सनरूफ को खोला नहीं जा सकता। एमजी मोटर ने विंडसर ईवी की तकनीकी विशेषताओं का अभी खुलासा नहीं किया है। हालांकि यह फास्ट चार्जिंग कम्पैटिबिलिटी और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 50.6 kWh बैटरी पैक से लैस होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। JSW MG Motor ने आगामी इलेक्ट्रिक वाहन Windsor EV का नया टीजर जारी किया है। इसे अगले कुछ हफ्तों में भारत में लॉन्च किया जाना है। ब्रिटिश मूल की कार निर्माता कंपनी 11 सितंबर को भारतीय बाजार में Windsor EV लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नवीनतम टीजर वीडियो से पता चलता है कि इसमें कई एडवांस फीचर्स के अलावा एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी होगा।

फिक्स्ड ग्लास रूफ के साथ मारेगी एंट्री

टीजर से पता चलता है कि MG Windsor EV सिंगल-पैन फिक्स्ड ग्लास रूफ के साथ आएगी। इसका मतलब है कि सनरूफ को खोला नहीं जा सकता। MG मोटर ने सनरूफ को टीज करते हुए इसे इनफिनिटी व्यू ग्लास रूफ कहा है, जो इस सेगमेंट में पहली बार होगा।

संभावित फीचर्स

विंडसर ईवी में अन्य फीचर्स के अलावा एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग और बहुत कुछ शामिल होने की उम्मीद है। विंडसर ईवी में एक और अनूठी विशेषता यह होगी कि इसमें पीछे की ओर झुकी हुई सीटें होंगी, जिन्हें 135 डिग्री के एंगल से पीछे की ओर धकेला जा सकता है।

बैटरी, मोटर और रेंज डिटेल

एमजी मोटर ने विंडसर ईवी की तकनीकी विशेषताओं का अभी खुलासा नहीं किया है। हालांकि, यह फास्ट चार्जिंग कम्पैटिबिलिटी और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 50.6 kWh बैटरी पैक से लैस होने की उम्मीद है। विंडसर ईवी एक बार चार्ज करने पर 460 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है और डीसी फास्ट चार्जर का उपयोग करके आधे घंटे के अंदर 30 प्रतिशत से पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगी।

2025 एमजी एस्टॉर की पहली झलक आई सामने, हाइब्रिड इंजन के साथ जल्द मारेगी एंट्री

परिवहन विशेष न्यूज

Updated Astor या ZS की नई पीढ़ी को हाइब्रिड तकनीक मिल सकती है। नए हाइब्रिड पावरट्रेन के अलावा MG Astor को एक व्यापक डिजाइन ओवरहाल भी मिलेगा। इस Compact SUV को अब MG3 और MG HS जैसे कुछ वैश्विक मॉडलों के समान एक स्पोर्टी लुक मिलेगा। उम्मीद है कि MG Astor में इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा।

नई दिल्ली। नेक्स्ट जेनरेशन MG Astor को ग्लोबल लॉन्च से पहले टीज किया गया है। इसे वैश्विक स्तर पर MG ZS के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि Astor या ZS की नई पीढ़ी को हाइब्रिड तकनीक मिल सकती है। हाल ही में सामने आए स्पाई वीडियो में इसके पीछे 'Hybrid+' बैजिंग दिखी है।

2025 MG Astor में क्या नया?

अपडेटेड MG Astor Hybrid+ के कोर में एक सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम होगा। MG3 में पाए जाने वाले सिस्टम की तरह, यह सिस्टम पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एटकिंसन साइकिल पर चलेगा। नया हाइब्रिड सिस्टम 1.83 kWh NCM लिथियम-आयन बैटरी पैक का उपयोग करता है।

डिजाइन अपडेट

नए हाइब्रिड पावरट्रेन के अलावा, MG Astor को एक व्यापक डिजाइन ओवरहाल भी मिलेगा। इस Compact SUV को अब MG3 और MG HS जैसे कुछ वैश्विक मॉडलों के समान एक स्पोर्टी लुक मिलेगा। बाहरी बदलावों की मुख्य विशेषताओं में नए एलईडी हेडलाइट्स और ग्रिल के साथ नया फ्रंट फेसिया, साथ ही नए डिजाइन किए गए बंपर और एयर इनटेक शामिल हैं।

अपडेट किए गए एलॉय व्हील, टेल लाइट और रियर बंपर भी अपडेट किए गए बाहरी स्टाइल का हिस्सा हैं। कंपनी ने कहा है कि ड्राइविंग डायनेमिक्स को बेहतर बनाने के लिए MG Astor में चेसिस रिफाइनमेंट भी किया गया है।

इंटीरियर और फीचर्स

उम्मीद है कि MG Astor में इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा। अपडेट किए गए MG Astor की अन्य अपेक्षित विशेषताओं में पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और नई फंक्शनलिटी के साथ ADAS मिलने वाला है।

अपडेट की गई MG Astor या MG ZS को सितंबर 2023 में यूरोपीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। जबकि भारतीय लॉन्च 2025 में होने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल की तरह अपडेट की गई MG Astor भी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Hyundai Creta, Kia Seltos और यहां तक कि Citroen Basalt और Tata Curvv जैसी एसयूवी को टक्कर देगी।

समय की सबसे बड़ी मांग अक्षय ऊर्जा

योगेश कुमार गोयल

अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है, जो असीमित और प्रदूषणरहित है या जिसका नवीकरण होता रहता है। ऊर्जा के ऐसे प्राकृतिक स्रोत, जिनका क्षय नहीं होता, अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। अक्षय ऊर्जा के महत्त्वपूर्ण स्रोतों में सूर्य, जल, पवन, ज्वारभाटा, भूताप इत्यादि प्रमुख हैं। उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा को ही लें। सूर्य सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसकी रोशनी स्वतः ही पृथ्वी पर पहुंचती रहती है'

पूरी दुनिया में पारंपरिक ऊर्जा के मुकाबले अक्षय ऊर्जा की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। दरअसल वर्तमान में पूरी दुनिया पर्यावरण संबंधी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इस समस्या को और ज्यादा विकराल बनाने में सहभागी बन रहे हैं जबकि अक्षय ऊर्जा इन गंभीर चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित हो सकती है। यही कारण है कि भारत में भी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को 'श्योर, प्योर और सिक्योर' बताते हुए अक्षय ऊर्जा के महत्व को स्पष्ट रेखांकित कर चुके हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत की यह बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि भारत दुनियाभर में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। देश में अक्षय ऊर्जा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। प्रदूषणकारी और सीमित मात्रा में उपलब्ध पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय अक्षय ऊर्जा से ही ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए अब देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली के कारण वातावरण में प्रतिवर्ष लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन के मामले में यह संतोषजनक स्थिति ही है कि भारत इस मामले में दुनिया का चौथा देश है और नई-नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक के पावगाड़ा में दो हजार मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर पार्क सहित देश में रीवा से भी ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे कुछ और सोलर पार्क भी देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बहरहाल, अक्षय ऊर्जा को लेकर यह जानना बहुत जरूरी है कि अक्षय ऊर्जा आखिर है क्या और इसके स्रोत कौन से हैं? अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है, जो असीमित और प्रदूषणरहित है या जिसका नवीकरण होता रहता है। ऊर्जा के ऐसे प्राकृतिक स्रोत, जिनका क्षय नहीं होता, अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। अक्षय ऊर्जा के महत्त्वपूर्ण स्रोतों में सूर्य, जल, पवन, ज्वारभाटा, भूताप इत्यादि प्रमुख हैं। उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा को ही लें।

सूर्य सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसकी रोशनी स्वतः ही पृथ्वी पर पहुंचती रहती है। यदि हम सूर्य की इस रोशनी को सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं भी करते हैं, तब भी यह रोशनी तो पृथ्वी पर आती ही रहेगी लेकिन क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली इस असीमित ऊर्जा के उपयोग से न तो यह ऊर्जा घटती है और न ही इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, इसीलिए सूर्य से प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन से बचाव के दृष्टिगत ही आज अक्षय ऊर्जा को अपनाना समय की सबसे बड़ी मांग है। दरअसल पूरी दुनिया इस समय पृथ्वी के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बेहद चिंतित है, इसीलिए कोयला, गैस, पेट्रोलियम पदार्थों जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बजाय अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। भारत सहित कई प्रमुख देशों में अब थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के इस्तेमाल को कम करते हुए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के महत्त्वपूर्ण स्रोतों का उपयोग किया जाने लगा है। दरअसल आज स्वच्छ वातावरण के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों के बजाय क्लीन और ग्रीन एनर्जी की पूरी दुनिया को जरूरत है और इन्हीं जरूरतों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री 'वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड' की बात करते हुए इस ओर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा करीब साढ़े तीन दशक पूर्व पवन ऊर्जा से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की शुरू की गई पहल के बाद से देश की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ चुकी है। चीन, अमरीका और जर्मनी के बाद भारत अब पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भी चौथे स्थान पर है। फिलहाल जिस प्रकार देश में शुद्ध, सुरक्षित और भरोसेमंद ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि अगले कुछ दशकों में देश की कोयला, गैस इत्यादि प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों से ऊर्जा पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावॉट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक देश के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करने तथा वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हाल ही में मूडीज रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना है और भारत को 2030 तक इस अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए 385 बिलियन डॉलर का निवेश करना होगा। मूडीज के अनुसार भारत हालांकि 2022 तक 175 गीगावाट के अपने लक्ष्य से चूक गया था लेकिन 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को प्रतिवर्ष 50 गीगावाट बढ़ाने की योजना है और मूडीज के अनुमान के मुताबिक 44 गीगावाट की वार्षिक क्षमता वृद्धि भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। मूडीज का कहना है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को आगामी 6-7 वर्षों में 190-215 बिलियन डॉलर तथा ट्रांसमिशन और वितरण पर 150-170 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। मूडीज के मुताबिक भारत के मजबूत नीतिगत समर्थन ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को करीब 43 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, साथ ही निजी क्षेत्र के निवेश को भी आकर्षित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा में लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला अगले 10 वर्षों तक बिजली उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मूडीज का कहना है कि उसे उम्मीद है कि भारत अगले पांच से छह वर्षों में कोयला आधारित क्षमता में प्रतिवर्ष 40-50 गीगावाट जोड़ेगा, जिससे बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो इस अवधि में 5-6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढने की संभावना है। बहरहाल, आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाने के लिए काफी कार्य करना होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि डेढ़ दशक बाद भारत में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना तक बढ़ सकती है। आज न केवल भारत बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही ऐसा विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने कारगर होगी।

संपादक की कलम से

आरक्षण की छद्म राजनीति

आरक्षण पर फर्जी, छद्म, झूठी, अतार्किक कहानियां गढ़ी जा रही हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरक्षण और उसके आधार संविधान के जरिए मोदी-विरोध की राजनीति कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में उनका यह 'हथियार', कमोबेश उप्र और महाराष्ट्र में, कारगर साबित हुआ। राजस्थान में भी भाजपा को कुछ हद तक नुकसान झेलना पड़ा। अब उपचुनावों और राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी वे इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। न तो संविधान को खत्म किया जा सकता है और न ही आरक्षण छीना जा सकता है, इसे देश को 'ब्रह्मसत्य' मानना चाहिए। यदि दलित, आदिवासी और ओबीसी के किसी बच्चे को, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, आरक्षण की सुविधा न मिले और पहली नौकरी के समय आरक्षण की अनिवार्यता लागू न की जाए, तो वह आरक्षण-विरोध है। उस पर आंदोलित भी होना चाहिए और अदालत का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार जिन शीर्ष पदों पर 'विशेषज्ञों' की सीधी भर्ती करना चाहती है, वे सामान्य आरक्षण के दायरे में नहीं हैं। संयुक्त सचिव 10 और निदेशक/उपसचिव की 35 भर्तियां सरकार करेगी। उसका विज्ञापन भी सार्वजनिक किया गया है। यह कवायद पहली बार नहीं की जा रही है। इस सूची में पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का नाम भी है, जिन्हें 'विशेषज्ञ अर्थशास्त्री' के कारण तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया था। फिर 'योजना आयोग' का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 1991 में जब वह केंद्रीय वित्त मंत्री बने, तो वित्त सचिव के पद पर उन्होंने मोंटेक सिंह आहलूवालिया को मांगा था। मोंटेक आईएएस नहीं थे, फिर भी देश के वित्त सचिव बनाए गए। बाद में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार में उन्हें 'योजना आयोग' का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इसी सूची में रघुराम राजन, विमल जालान, नंदन नीलेकणि, सैम पित्रोदा, एनटीपीसी के चेयरमैन रहे पी. कपूर आदि सैकड़ों नाम दर्ज हैं, जिन्हें सरकार ने सीधे ही नौकरशाही के वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया था।

ऐसी नौकरियां 1968 से दी जा रही हैं और अधिकतर कांग्रेस सरकारों के दौरान ही दी गई हैं। तब संविधान को खत्म करने और आरक्षण को छीनने के मुद्दे नहीं उठाए गए। अब भी सीधी भर्ती वाले 57 शीर्ष अधिकारी भारत सरकार में कार्यरत हैं। इन भर्तियों से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि के युवा दावेदार कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। यह मुद्दा राहुल गांधी बार-बार उठा रहे हैं। भारत सरकार में जो अधिकारी आज सचिव के पद पर हैं, वे 1990 के दशक में आईएएस बने होंगे। आरक्षण तब लागू हुआ होगा, नतीजतन 3-4 सचिव आज अनुसूचित जाति और जनजाति के भी हैं। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। संघ लोक सेवा आयोग की अपनी स्वायत्तता है। लोकतंत्र में जनादेश ही अधिकार देता है। जनादेश से जिसकी सत्ता बनी है और प्रधानमंत्री, कैबिनेट आदि तय हुए हैं, तो संविधान उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी देता है। पहले तो प्रधानमंत्री ही तमाम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करते थे। अब कमोबेश नेता प्रतिपक्ष भी चयन समिति के सदस्य हैं। लिहाजा सीधी भर्तियां भी सरकार कर सकती है। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यदि विपक्ष को कुछ गलत लगता है, तो वह सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे सकता है। सचिव की बात छोड़ भी दें, तो संयुक्त सचिव पद के लिए भी कमोबेश 15 साल का अनुभव अनिवार्य है। निदेशक/उपसचिव के लिए भी 10 साल का अनुभव जरूरी है। जो युवा आज आईएएस बन रहे हैं अथवा बनना चाहते हैं, उन्हें शुरुआती दौर में एसडीएम या सहायक कलेक्टर आदि पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। सरकार अपेक्षाकृत वरिष्ठ पदों पर विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाना चाहती है। ऐसे विशेषज्ञ भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के हो सकते हैं। आरक्षण को इतना संकीर्ण न बनाया जाए और न ही देश को गुमराह किया जाए, क्योंकि ऐसी राजनीति 'क्षणिक' होती है।

राय

आर्थिक डेस्टिनेशन-3

हिमाचल की आर्थिक तरक्की के सलाहकार बदलते रहे हैं, बल्कि सियासी प्राथमिकताओं ने अच्छी नीतियों का भी आखेट किया। योजनाएं-परियोजनाएं ध्वस्त होती गईं, क्योंकि सरकारों में 'मिशन रिपीट' जैसे संकल्पों पर कार्य किया। रोजगार को सरकारी नौकरी और समाज को लाभार्थी बनाने के नाम पर राज्य का बजट अपने पैमानों और अपने नजरानों पर भटक गया। नतीजतन कर्ज की डूब में संभावनाओं की दृष्टि और आर्थिक क्षमता का विकास असंभव होता चला गया। जहां आर्थिक स्रोत हैं वहां भी उत्तम सलाहकार नहीं। स्व. ठाकुर कर्म सिंह के बाद कोई स्वतंत्र प्रभार से वित्त मंत्री नहीं रहा, नतीजतन मुख्यमंत्रियों के वित्त सलाहकार के रूप में नौकरशाही का परचम अर्थ व्यवस्था की निरंतरता की बजाय पांच साल के पर्याय में एक प्रहसन बनता गया। आखिर आर्थिकी चलाते कौन और आज की तारीख में जीएसटी आता कहां से। सीमेंट उद्योग, परिवहन, पर्यटन, रिटेल स्टोर, लघु और मध्यम उद्योग, बिल्डिंग मैटीरियल और बाजार से आने वाला राजस्व वास्तव में हमारी आर्थिक रीढ़ है। क्या हमने इन्हें प्रदेश की आर्थिकी का संबल माना। क्या प्रदेश का सरकारी ढांचा निजी क्षेत्र को उचित स्थान दे पाया। किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र का स्थान अहमियत रखता है, इसलिए हर मंत्री को अपनी विभागीय कसरतों का सौहार्द निजी क्षेत्र की संभावना से जोडऩा चाहिए। अगर हम परिवहन क्षेत्र को ही लें तो कुल पंजीकृत वाहनों की 24 लाख की तादाद में आर्थिकी व रोजगार के पहिए भी घूम रहे हैं। कोई ट्रक या टैक्सी चालक सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिकी का सेतु भी है।

क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि इस वर्ग से तालमेल बना कर परिवहन का माहौल बेहतर कैसे करें। माल ढुलाई की दरों में प्रदेश के व्यापार की आधी शक्ति चली जाती है। टैक्सी दरों में पर्यटन उद्योग की संभावना आधी हो जाती है। भविष्य के निजी ट्रक, बसें व टैक्सियां कैसी होंगी या प्रदेश के परिवहन को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र को क्या अहमियत मिलनी चाहिए, इसके लिए सलाहकार बोर्डों में गैर राजनीतिक, लेकिन प्रोफेशनल लोगों को जगह मिलनी चाहिए। पिछले दिनों एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक सरकारी बसों से ही उनकी बिगड़ी हालत का कारण पूछ रहे थे। अगर आज भी एचआरटीसी को सुधारना हो तो परिवहन मंत्री को अपने सलाहकारों में निजी बस आपरेटरों को शामिल कर लेना चाहिए। सरकारी स्कूलों की गरिमा बढ़ानी हो, तो शिक्षा मंत्री को अपने सलाहकार बोर्ड में निजी स्कूलों के प्रबंधकों को जोड़ लेना चाहिए। ताज्जुब यह कि अब तो स्वास्थ्य मंत्री को अगर अपने सरकारी अस्पताल ठीक से चलाने हैं या चिकित्सा के ढर्रे को सुधारना है, तो निजी क्षेत्र की सफलता के मानदंड सीखने के लिए उनके कर्ता धर्ताओं से सलाह लेनी होगी। प्रदेश के होटल व्यवसायियों, ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों तथा इवेंट कंपनियों के संचालकों के साथ एक बार बैठें, तो पर्यटन उद्योग की शक्ल और सूरत बदल सकती है। इसी तरह राज्य के विभिन्न व्यापार मंडलों के साथ बैठकर सरकार स्थानीय निकायों के लक्ष्य, भविष्य के संवाद और सहभागिता बदल सकती है।

माहौल बनाओ, छात्रों का प्लायन रोको

प्रातःकालीन सभा किसी भी स्कूल का आईना होती है। जितनी बेहतर यह सभा होगी, उतनी बेहतर उस स्कूल की छवि समाज में बनती है। इस समय छात्रों का टर्नऑऊट व क्रियाकलाप कैसा है, इस बात का ध्यान रखना अध्यापकों का दायित्व बन जाता है। यह समय अध्यापकों के लिए छात्रों से संवाद करने का सबसे बढ़िया मौका होता है'

आज स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है, वर्दी मुफ्त है, भोजन मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, स्कॉलरशिप है, परंतु हालात-ए-हाजिर बताते हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूल घटती हुई छात्र संख्या की समस्या से दो-चार है। सोचा क्या था और हो क्या गया, ये परेशानी का सबब है। निस्संदेह कोई भी नीति बेहतरी के लिए ही बनाई जाती है, परंतु परिणाम सफलता-असफलता तो जमीनी कार्यान्वयन व प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। शिक्षा नीति कोई भी हो, अमलीजामा तो उसे स्कूल में कार्यरत अध्यापक ने पहनाना है। ग्राउंड जीरो पर तैनात वह क्या करता है, यही शिक्षा की दशा को निर्धारित करता है। सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या का एक बहुत बड़ा तत्त्व है स्कूलों की साख, जो माहौल और वर्क कल्चर पर निर्भर करती है। यदि माइक्रो लैवल पर हर एक स्कूल छोटी-छोटी बातों पर खुद का ध्यान केंद्रित करे, तो निस्संदेह स्थिति सुधरने की संभावना है क्योंकि छोटे-छोटे सुधार ही बड़े-बड़े सुधारों के आधार बनते हैं। वो ऐसा है कि किसी स्कूल में सवेरे छात्रों के प्रवेश से ले कर उनके गृह प्रस्थान तक जो-जो भी घटता और चलता है, उसकी खबर हर शाम उतने घरों तक पहुंचती है, जितने घरों के बच्चे वहां पढने आते हैं। इस तरह समाज में उस स्कूल की एक छवि बन जाती है। ये बात हर अध्यापक को गांठ बांध लेनी चाहिए कि अन्य विभागों के दफ्तरी समय की तरह स्कूलों का कार्य शुरू नहीं होता, बल्कि पहली घंटी बजने के साथ हो जाता है। उससे भी पहले कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उदाहरणतः यदि स्कूल का समय दस बजे का है, तो बहुत से छात्र साढ़े नौ बजे के आसपास ही स्कूल पहुंच जाते हैं क्योंकि छात्र विभिन्न क्षेत्रों से बसों में आते हैं जिनका समय अलग-अलग होता है। इस बीच स्कूल में अगर कोई देखरेख करने वाला अध्यापक मौजूद नहीं है, तो जाहिर है अव्यवस्था का माहौल होगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बचकानी हरकतें कर सकते हैं। यही वह समय होता है, जब छात्र अवांछित गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, जिनमें लड़ाई-झगड़ा, नशे का सेवन, छात्राओं से छेडख़ानी की घटनाएं शामिल हैं।

ऐसे में अच्छे छात्रों की भी इन गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती हैं और चमकते हुए चांद टूटे हुए सितारे बन जाते हैं, क्योंकि सभी छात्र इतने परिपक्व तो नहीं होते कि रहीम जी के चंदन के वृक्ष बन जाए, जिन पर भुजंगों का असर नहीं होता। बहुत से सेब की तरह भी होते हैं, जो एक सड़े हुए सेब की सोहबत में सड़ जाते हैं। अतः विद्यालय प्रमुख को चाहिए कि दैनिक आधार पर बारी-बारी से अध्यापकों को सवेरे छात्रों की निगरानी के लिए तैनात करे। प्रातःकालीन सभा किसी भी स्कूल का आईना होती है। जितनी बेहतर यह सभा होगी, उतनी बेहतर उस स्कूल की छवि समाज में बनती है। इस समय छात्रों का टर्नऑऊट व क्रियाकलाप कैसा है, इस बात का ध्यान रखना अध्यापकों का दायित्व बन जाता है। यह समय अध्यापकों के लिए छात्रों से संवाद करने का सबसे बढिया मौका होता है। कक्षा में ही नहीं, कक्षा के बाहर आध्यापकों का छात्रों से संवाद का लहजा कैसा है, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्रातः कालीन सभा पर स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों की नजर रहती है। यह स्कूल के हर अध्यापक का कत्तव्य है कि वह छात्रों से संवाद करे व उनके सर्वांगीण विकास में मदद करें। प्रातःकालीन सभा के क्रियाकलाप जैसे समाचार वाचन, भाषण, प्रार्थना, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत यदि बेहतरीन हो जाए, तो स्कूल की छवि में चार चांद लग जाते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में स्कूल के बारे में सकारात्मक संदेश जाता है। इसी तरह छुट्टी का समय भी महत्त्वपूर्ण है। इस समय अध्यापकों का छात्रों से पहले कक्षा से बाहर आना अखरता है और यह भी एक अराजक स्थिति पैदा करता है। सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों के स्कूल से बाहर निकलने से पहले अध्यापक स्कूल न छोड़ें। यह सुनिश्चित हो कि छात्र तरतीब से बाहर निकले अर्थात कक्षावार बाहर निकलें न कि एक साथ। इन बातों पर विद्यालय प्रमुख की निगरानी नित्तांत आवश्यक है।

अध्यापक के छुट्टी पर होने से खाली कक्षाओं का समायोजन नियमित रूप से होना चाहिए। जब कोई वैकल्पिक विषय का पीरियड होता है, तो अकसर छात्र कमरे बदलते हैं। उस समय भी अध्यापक सुनिश्चित करें कि छात्रों की आवाजाही के बाद ही कक्षा से बाहर आएं अन्यथा रोज अफरा तफरी का माहौल बना रहेगा। ये बात भी जरूरी है कि स्कूलों में छात्रों के बहुआयामी विकास के लिए गतिविधियां होती रहें। जहां संख्या माकूल है, वहां छात्रों को विभिन्न सदनों में बांटा जाए और अंतर सदन प्रतियोगिताओं के आयोजन में अध्यापक निरंतर रुचि दिखाएं। कम संख्या वाले स्कूलों में अंतर कक्षा स्पर्धाएं करवाई जा सकती हैं। विभिन्न अंतर विद्यालय खेल, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में स्कूल का क्या प्रदर्शन रहता है, इस बात से भी स्कूल की छवि बनती है। विद्यालय में चल रही एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, एन सी सी, इको क्लब इत्यादि इकाइयों का निरंतर क्रियाशील होना भी आवश्यक है। कहीं फोटो खींच कर ही इतिश्री करने का काम तो नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी अध्यापक डिमोटिवेटिड सा हो गया है। अतः जिला व राज्य स्तर पर समय-समय पर अध्यापकों के लिए मोटिवेशनल कार्यशाला या सेमिनार का आयोजन किया जाए। हर विद्यालय से एक अध्यापक को इस कार्य के लिए तैयार किया जाए व हर स्कूल में एक मोटिवेशनल सैल हो। माना सरकारी स्कूलों में छात्रों विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा हर माता-पिता की चाहत होती है। यदि उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही, तो गरीब होते हुए भी वे अपना पेट काट कर अपने बच्चे को अधिक फीस वाले प्राइवेट स्कूल भेजना चाहेंगे। अतः हर अध्यापक को अपने-अपने स्तर पर जुगत लगानी होगी, अन्यथा स्कूल की घंटी नहीं बल्कि स्कूल से घंटी बज जाएगी।

जगदीश बाली

पीए सिद्धार्थ

कुरसी पर बंदर

उत्तर प्रदेश की पुलिस अकसर चर्चाओं में बनी रहती है। कभी लाठी के ऊपर घुड़सवारी की प्रेक्टिस के कारण तो तो कभी मुंह से गोलियां चला कर। कभी उदंड कांवडियों पर हेलिकाप्टर से फूल बरसा कर तो कभी फजऱी एनकाऊंटर में लोगों को गोली का निशाना बना कर। उसे नेताओं की तरह किसी न किसी बहाने चर्चा में बने रहने का पुराना अभ्यास और अनुभव जो है। लेकिन फिलहाल चर्चा है अयोध्या राम जन्मभूमि थाने के कोतवाल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपनी कुरसी पर बंदर को बिठा कर सलामी देने की। कोतवाल बाकायदा बावर्दी अपने नंग-धडंग पूर्वज को सलाम ठोक रहे हैं। फोटो अखबारों में छपे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। खैर! पुलिस को अपने सीनियर को सलाम ठोकने के अलावा नेताओं को सैल्यूट मारने होते हैं। अपने सीनियर को पुलिस वाले उनकी वरिष्ठता के हिसाब से सलाम ठोकते हैं। लेकिन नेताओं को पुलिस अपना पूर्वज समझ कर सलाम ठोकती है या फिर उनका रुतबा देख कर। पहले आम आदमी को यह समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। पर आज़ादी के अमृत काल में सत्ताधीशों ने अपनी हरकतों से जिस तरह आदमी और बंदर के बीच की खाई को सफलता से पाटा है, उससे तो यही लगता है कि राम जन्मभूमि थाना के कोतवाल साहिब की बंदर को दी गई सलामी बेकार नहीं गई। हो सकता है उनकी इस सफलता को देखते हुए जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी साहिब या मुख्य मंत्री स्वयं पहल करते हुए राष्ट्रपति पदक के लिए कोतवाल साहिब के नाम की अनुशंसा कर दें। इस बात की भी पूरी संभावना है कि हनुमान को आदिवासी बताने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी कोतवाल साहिब की इस हनुमान भक्ति को देखते हुए उन्हें यूपीएसी की लेट्रल एंट्री की तरह पिछले दरवाजे से राज्य के डीजीपी के पद पर बिठा दें। संभावनाएं अपार हैं।

हो सकता है कि उनकी इस हनुमान भक्ति को देखते हुए केंद्र सरकार उन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दे या कैंद्रीय विश्वविद्यालय का वीसी बना दे। अगर किस्मत ज्यादा मेहरबान हुई तो उप राष्ट्रपति का पद भी मिल सकता है। राष्ट्रपति होने की काबिलीयत थोड़ी अलग है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने बंदर की प्रशंसा में लिखा है कि बंदर में हमें इसके इलावा और कोई ऐब नजऱ नहीं आता कि वो इनसान का जद्द-ए-आला (पूर्वज) है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने तीन बंदरों को प्रतीक बना कर बुरा न सुनने, बुरा न बोलने और बुरा न कहने के सिद्धांत को समाज के सामने रखा था। लेकिन भारतीयों ने बापू की अन्य बातों की तरह उनके इन तीन सिद्धांतों को भी हवा में उड़ा दिया। बस याद रखा तो उनके बंदरों को और उन्हें इज़्ज़त देते हुए कुरसियों पर बिठा दिया। चाल्स डार्विन ने थ्येरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया है कि हम कैसे बंदर से इंसान बने। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। उनमें आए बदलाव उनके आगे की पीढ़ी में दिखने लगे। पर मेरा मानना है कि आदमी के अंदर का बंदर अभी भी ज़िंदा है और मौका देख कर बाहर आ जाता है। फिर चाहे वह झोंपड़ी में रहे या राष्ट्रपति भवन में। ट्रंप की हरकतों से कभी नहीं लगा कि उनके भीतर का बंदर वाशिंगटन छोड़ कर गया है। सदन की कार्यवाही का लाईव प्रसारण देख कर शहर में होने का भ्रम समाप्त हो जाता है। अपनी इस हीन ग्रंथि से छुटकारा पाने के लिए नेताओं ने एनसीईआरटी की नौवीं और दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम से चाल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को हटवा दिया ताकि हमें याद न रहे कि कभी हमारे पूर्वज बंदर थे। लेकिन सवाल है कि आदमी उन हरकतों से कैसे छुटकारा पा सकता है जो आज भी उसके बंदर होने का प्रमाण देती हैं। इतिहास में अपने अनुकूल बदलाव किए जा सकते हैं। पर क्या आदतों और हरकतों में बदलाव करना संभव है। अगर होता तो कोतवाल साहिब बंदर को कुरसी पर बिठा कर सलाम क्यों ठोकते।

क्या अब दलहन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बुवाई का रकबा 6 फीसदी बढ़ा

मौजूदा सत्र के 20 अगस्त तक दलहन की बुवाई का रकबा बढ़कर 120 .18 लाख हेक्टेयर हो गया जो पिछले साल इसी अवधि में 113 .69 लाख हेक्टेयर था। अरहर की बुवाई का रकबा 40 .74 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 .78 लाख हेक्टेयर हो गया। उड़द की बुवाई का रकबा भी बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दलहन में आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मौजूदा 2024-25 खरीफ (ग्रीष्म) सत्र में अब तक धान का रकबा छह प्रतिशत बढ़कर 369.05 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह एक साल पहले की अवधि में 349.49 लाख हेक्टेयर था। यह जानकारी कृषि मंत्रालय ने दी है। मुख्य खरीफ फसल धान की बुवाई जून में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है और सितंबर से कटाई होती है।

दलहन का रकबा बढ़ा

मौजूदा सत्र के 20 अगस्त तक दलहन की बुवाई का रकबा बढ़कर 120.18 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 113.69 लाख हेक्टेयर था। अरहर की बुवाई का रकबा 40.74 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45.78 लाख हेक्टेयर हो गया। 'उड़द' की बुवाई का रकबा 29.52 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28.33 लाख हेक्टेयर हो गया।

मोटे अनाज और 'श्री अन्न' (बाजरा) का रकबा एक साल पहले की समान अवधि के 176 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 181.11 लाख हेक्टेयर हो गया। मोटे अनाजों में मक्का का रकबा 81.25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 87.23 लाख हेक्टेयर हो गया। तिलहन की बुवाई का रकबा इस खरीफ सीजन में मामूली रूप से बढ़कर 186.77 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 185.13 लाख हेक्टेयर था।

गन्ने की बुवाई भी बढ़ी

नकदी फसलों में गन्ने की बुवाई का रकबा 57.11 लाख हेक्टेयर से मामूली रूप से बढ़कर 57.68 लाख हेक्टेयर हो गया। वहीं, कपास का रकबा 122.15 लाख हेक्टेयर से घटकर 111.07 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि जूट-मेस्ता का रकबा 6.56 लाख हेक्टेयर से घटकर 5.70 लाख हेक्टेयर रह गया।

सभी खरीफ फसलों की बुवाई का कुल क्षेत्रफल पिछले वर्ष की समान अवधि के 1,010.52 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक यानी 1,031.56 लाख हेक्टेयर रहा। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्तमान में सक्रिय है और अच्छी प्रगति कर रहा है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा दर्ज की गई है।

पिछले 25 सालों में भारतीय शेयर बाजार ने बर्कशायर हैथवे से बेहतर किया प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 25 सालों में प्रसिद्ध निवेश फर्म से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल भारतीय शेयरों ने मशहूर निवेशक वारेन बफे के बर्कशायर हैथवे के डालर के संदर्भ में 9 .52 प्रतिशत की तुलना में प्रति वर्ष 12 .56 प्रतिशत का वार्षिक रिटर्न हासिल किया। आइये इसके बारे में जानते हैं।

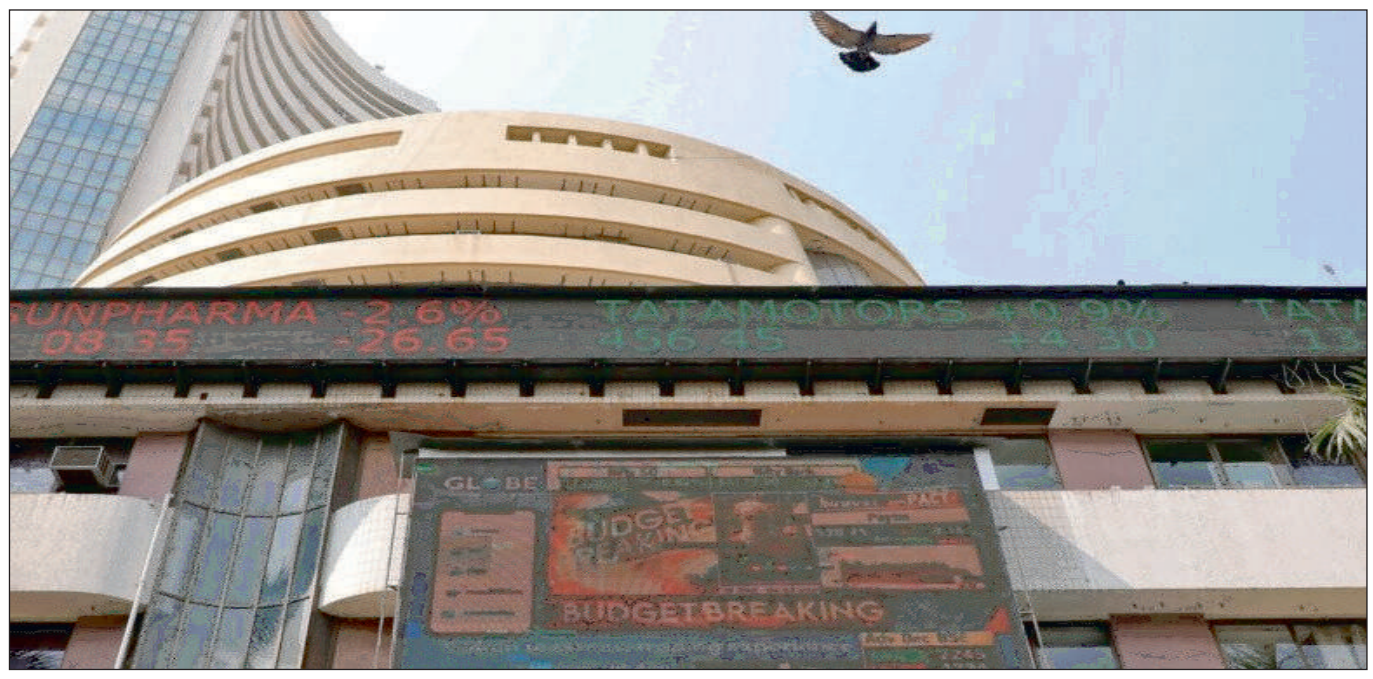

नई दिल्ली। राजनीतिक उथल-पुथल और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 25 सालों में बर्कशायर हैथवे जैसी प्रसिद्ध निवेश फर्म से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। सिंगापुर स्थित एसेट मैनेजमेंट कंपनी हेलिओस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल भारतीय शेयरों ने मशहूर निवेशक वारेन बफे के बर्कशायर हैथवे के 9.52 प्रतिशत की तुलना में प्रति वर्ष 12.56 प्रतिशत का वार्षिक रिटर्न हासिल किया और वह भी डालर के संदर्भ में।

भारतीय शेयर बाजार का यह प्रभावशाली प्रदर्शन समझदार निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश मार्ग के रूप में इक्विटी की क्षमता को उजागर करता है। शेयर बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, युवा जनसांख्यिकी, बढ़ता शहरीकरण और चल रहे सुधारों का संयोजन भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई संकटों और अस्थिरता का सामना करने के बावजूद, भारत ने दीर्घकालिक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।

आर्थिक परिदृश्य में कई संकट

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 25 वर्षों (31 जुलाई, 1999 से 31 जुलाई, 2024 तक) में भारतीय इक्विटी मार्केट इंडेक्स ने बर्कशायर हैथवे के शेयरों में निवेश करने से मिलने वाले रिटर्न से अधिक रिटर्न दिया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के आर्थिक परिदृश्य में कई संकट आए हैं, जिनमें आठ गठबंधन सरकारें, 1996 और 1998 के बीच तीन बार सरकार बदलना, एक सरकार जो केवल 13 दिनों तक चली, मई 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिकी प्रतिबंध, उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध और कई वैश्विक घटनाएं शामिल हैं, फिर भी देश के इक्विटी बाजार ने लगातार लचीलापन और बेहतर प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है।

गठबंधन सरकारों की मजबूरियों और बाजार के झटकों से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और आतंकवादी हमलों तक, भारत ने विकास की गति को बनाए रखते हुए कई तूफानों का सामना किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का परीक्षण

ऐतिहासिक रूप से, भारत ने 1997 में एशियाई संकट, 2004 में रूसी संकट सहित 1998 और 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। इनमें से प्रत्येक घटना ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का परीक्षण किया और बाजारों ने वापसी की, जिससे उबरने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

उदाहरण के लिए, सरकार में अचानक बदलाव के कारण 2004 में 17 प्रतिशत बाजार में गिरावट के बावजूद, अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहा, क्योंकि निवेशकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित क्षमता को पहचाना। रिपोर्ट में कहा गया है कि संकटों, घटनाओं और अस्थिरता के बावजूद भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया।

2011 से 2015 की अवधि में भ्रष्टाचार के घोटाले और लगातार सूखे जैसी कई चुनौतियाँ सामने आईं। हालाँकि, इन संकटों ने निवेशकों के भरोसे को कम नहीं किया। रिपोर्ट कहती है कि कई संकटों और अस्थिरता का सामना करने के बावजूद, भारत ने दीर्घकालिक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।

शेयर बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, युवा जनसांख्यिकी, बढ़ते शहरीकरण और चल रहे सुधारों का संयोजन भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करता है, जो महत्वपूर्ण विकास के अवसरों को अनलॉक करते हुए चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।

आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था को छोड़ना हो सकता है जोखिम भरा, कुछ बदलावों की है गुंजाइश

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार ने आरबीआई को दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने नीतिगत ब्याज दर तय करते समय खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर रखने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि मौद्रिक नीति का खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था ने अच्छा काम किया है और इसे अधिक विवेकाधीन व्यवस्था के पक्ष में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक नए रिसर्च पेपर में यह बात कही गई है। रिसर्च पेपर के मुताबिक, अगर आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था को छोड़ता है, तो यह जोखिम भरा और प्रतिकूल साबित हो सकता है।'

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यः एक और आकलन' शीर्षक वाले इस शोध पत्र में कहा गया कि भारतीय परिवारों की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का भार कम करना चाहिए। इसमें कहा गया, 'आरबीआई की मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था ने अच्छा काम किया है। ऐसे में इसे व्यापक बनाने या अधिक विवेकाधीन व्यवस्था के पक्ष में लक्ष्य को छोड़ने जैसे बदलाव जोखिम भरे और प्रतिकूल होंगे।'

मुद्रास्फीति का 4 फीसदी वाला लक्ष्य उचित

इस रिसर्च पेपर के लेखक अर्थशास्त्री बैरी आइशेनग्रीन (कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले) और पूनम गुप्ता (एनसीएईआर) हैं। इसमें आगे कहा गया कि दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत मुद्रास्फीति का लक्ष्य व्यापक रूप से उचित है। शोध पत्र में कहा गया है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को लेकर आरबीआइ और सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, उसने लगभग सभी मामलों में आशा अनुरूप प्रदर्शन किया है।

पत्र में कहा गया है कि यह केवल एक बार हुआ है कि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों (जनवरी 2022-सितंबर 2022 के दौरान) में छह प्रतिशत की ऊपरी सहनीय सीमा के पार रही है।

खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर रखने की वकालत

हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने नीतिगत ब्याज दर तय करते समय खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर रखने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि मौद्रिक नीति का खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है और इसके दाम काफी कुछ आपूर्ति पक्ष के अनुरूप तय होते हैं। बता दें कि सरकार ने आरबीआइ को दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है।

टेलीकॉम, मेटल और माइनिंग सेक्टर में आएगी बहार; सालाना 50 अरब डॉलर का निवेश करेंगी कंपनियां

भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले कई तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ 8 फीसदी से अधिक रही है। हालांकि इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए खपत रोजगार और निर्यात पर खास फोकस करने की जरूरत होगी। इसमें भारतीय कंपनियों का योगदान काफी अहम रहने वाला है। खासकर रोजगार के मोर्चे पर भारतीय कंपनियों का रोल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

नई दिल्ली। मूडीज रेटिंग ने मंगलवार को कहा कि भारतीय कंपनियां क्षमता बढ़ाने के लिए अगले एक-दो साल में पूंजीगत व्यय के तहत सालाना 45 से 50 अरब डॉलर का निवेश करेंगी। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस व्यय में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत होगी। मूडीज ने भारत और इंडोनेशिया में सक्रिय कंपनियों के ऊपर जारी एक रिपोर्ट में कहा कि उत्पादन श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए निवेश किया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'अगले एक से दो साल में रेटिंग वाली भारतीय कंपनियों का सालाना पूंजीगत व्यय लगभग 45 से 50 अरब डॉलर तक रहेगा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी अकेले 30 प्रतिशत होगी। कंपनी ने विभिन्न कारोबार में निवेश को लेकर लगभग 15 अरब डॉलर का निर्धारण किया हुआ है।' इसके मुताबिक, तेल एवं गैस क्षेत्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर एक-दो साल में सामूहिक रूप से भारतीय कंपनियों के कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक खर्च करेंगी।

मूडीज ने कहा कि अगले दो साल में भारत की जीडीपी वृद्धि दर छह प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है। भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने में घरेलू मांग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मूडीज रेटिंग को उम्मीद है कि अगले एक-दो साल में रेटिंग वाली भारतीय कंपनियों की कमाई पांच प्रतिशत बढ़ेगी। धातु, खनन और इस्पात, दूरसंचार तथा वाहन कंपनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि से कंपनियों को लाभ होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले कई तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ 8 फीसदी से अधिक रही है। हालांकि, इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए खपत, रोजगार और निर्यात पर खास फोकस करने की जरूरत होगी। इसमें भारतीय कंपनियों का योगदान काफी अहम रहने वाला है। खासकर, रोजगार के मोर्चे पर भारतीय कंपनियों का रोल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

रक्षाबंधन के बाद सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल, क्या हाथ से निकल गया खरीदारी का सुनहरा मौका?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाने का एलान किया था। उसके बाद से दोनों धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। 23 जुलाई को सोना 3350 रुपये गिरकर 72300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। उसके बाद सोने और चांदी के भाव में ज्यादातर गिरावट ही देखी गई और कोई बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला।

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाने का एलान किया था। उसके बाद से दोनों धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। 23 जुलाई को सोना 3350 रुपये गिरकर 72300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। उसके बाद सोने और चांदी के भाव में ज्यादातर गिरावट ही देखी गई और कोई बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला।

नई दिल्ली। सोने के दाम में मंगलवार को तेज उछाल देखा गया। यह 1,400 रुपये बढ़कर 74,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में पहली बार सोने की कीमतों में इतनी अधिक तेजी देखी गई है। पिछले कारोबारी सत्र गोल्ड 72,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 3,150 रुपये बढ़कर 87,150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले बंद के 84,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाने का एलान किया था। उसके बाद से दोनों धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। 23 जुलाई को सोना 3,350 रुपये गिरकर 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। उसके बाद सोने और चांदी के भाव में ज्यादातर गिरावट ही देखी गई और कोई बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला।

क्यों बढ़े सोने के भाव

व्यापारियों का कहना है कि जौहरियों की ओर से डिमांड बढ़ी है और वैश्विक रुझान भी इस कीमती पीली धातु के हक में है। इस वजह से कीमतों में तेजी आ रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, "उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) ब्याज दरों में बड़ी कटौती करेगा। इससे निवेशक सोने पर काफी बुलिश हैं।"

कोटक सिक्योरिटीज के एवीपी-कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला के अनुसार, कॉमेक्स सोने की कीमतों ने सप्ताह की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ की, जो 2,549.90 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 2,541 डॉलर पर बंद हुई। उन्होंने कहा, ₹अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लचीलापन, भू-राजनीतिक तनाव और शिकागो फेड के अध्यक्ष की हालिया टिप्पणियों के बीच सोने की मांग बढ़ी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी भी 30.19 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। ₹सोना 2,500 डॉलर प्रति औंस से ऊपर स्थिर कारोबार कर रहा है।

शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के एसोसिएट वीपी, फंडामेंटल करेंसीज एंड कमोडिटीज प्रवीण सिंह के अनुसार, यूरो-जोन सीपीआई मुद्रास्फीति सहित प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा मंगलवार को बाद में जारी किया जाएगा जो बुलियन की कीमतों को दिशा प्रदान करेगा।

21 अगस्त को भारत बंद रहेगा, क्या है वजह- क्या खुलेगा और कौन-सी सेवाएं रहेंगी ठप?

परिवहन विशेष न्यूज

अगस्त यानी कल भारत बंद रहेगा। दरअसल एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न दलित संगठन 21 अगस्त को सड़कों पर उतरेंगे। इस बंद को कौन-सी राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं तो क्या-क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? जानने के लिए जानने के लिए पढ़िए...

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को 'भारत बंद' का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये हैं कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन-सा फैसला है, जिसका दलित संगठन विरोध कर हैं? दलित संगठनों की क्या मांगे हैं? संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरे में है? भारत बंद के दौरान क्या-क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, "सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए- सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले। ये दोनों जातियां एससी में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें एससी-एसटी आरक्षण का वर्गीकरण (सब-क्लासिफिकेशन) कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल-341 के खिलाफ नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकतीं। इसमें भी दो शर्त लागू होंगी।

गूगल ट्रेंड में भारत बंद

दलित संगठनों ने 21 अगस्त को 'भारत बंद' का आह्वान किया है। यह सुबह से ही गूगल पर ट्रेंड कर रहा है।

क्या हैं दो शर्त

एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकतीं।

एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था, जिनमें कहा गया था कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं।

कौन-कौन पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रहीं?

देशभर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का एलान किया है। इनको बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भारत आदिवासी पार्टी मोहन लात रोत का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता भी समर्थन में हैं।

किन राज्यों में भारत बंद के बारे में किया जा रहा सर्च?

भारत बंद को लेकर राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में इसके बारे में सर्च किया जा रहा है।

बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा,

"हम सब जानते हैं कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। बहन जी के दिशानिर्देश बीएसपी के सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि बीएसपी के नीला झंडा और हाथी निशान के तहत 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में शामिल हों और जनता को खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों तक उप वर्गीकरण के बारे में जागरूक करें।"

साथ ही उन्होंने अपील की कि बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित एवं संवैधानिक तरीके से बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल हों।

भारत बंद करने वालों की क्या मांगे हैं?

भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे।

भारत बंद के दौरान क्या बंद रहेगा?

भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। पुलिस-प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं।

भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद किए जा सकते हैं।

ये सेवाएं जारी रहेंगी

21 अगस्त को भारत बंद के दौरान अस्पताल और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसलिए बुधवार को बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, ऐसा माना जा रहा है।

भारत बंद के बारे में क्या सर्च किया जा रहा है?

देश में भारत बंद को लेकर लोग अलग-अलग कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं। जैसे- कल भारत क्यों बद रहेगा, भारत बंद, भारत बंद टुमोरो, कल भारत बंद है या नहीं आदि।

लेटरल एंट्री पर हंगामा क्यों मचा है?

यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती करना है। उद्देश्य है- प्रशासन में एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं और प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेटरल एंट्री के तहत सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप-सचिव की भर्ती होती है। केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को 45 अधिकारियों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थीं।

क्या लेटरल एंट्री में आरक्षण लागू नहीं होगा?

इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय का कहना है कि आयोग की ओर से निकाली गई लेटरल वैकेंसी में आरक्षण के वे नियम लागू होंगे, जो यूपीएससी की किसी भी दूसरे परीक्षाओं में लागू होते हैं।

वहीं भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है।

रोस्टर सिस्टम क्या है?

इसमें सरकारी नौकरी में हर चौथा पद ओबीसी, हर 7वां पद एससी, हर 14वां पद एसटी और हर 10वां पद ईडब्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि, तीन से कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता है।

बता दें कि सरकार ने कानूनी की तकनीकी वजहों का लाभ उठाते हुए अलग-अलग विभागों से तीन से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। हालांकि, आज सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती रद्द कर दी है।

21 अगस्त को भारत बंद के मध्यनजर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित

शाहपुरा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०सी०/एस०टी० वर्गो के आरक्षण को लेकर किये गये निर्णय के विरोध में दिनांक 21 अगस्त को भारत बंद को मध्यनजर रखते हुए नियंत्रण कक्ष में 4 कार्मिको की ड्यूटी लगाई गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील पुनिया ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01484-299056 है एवं नियंत्रण कक्ष में सहायक ऑफिस कानूनगो राकेश कुमार जैन तथा बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक गोविन्द सैनी की ड्यूटी प्रातः 08:00 से 10:00 बजे तक एवं ऑफिस कानूनगो बृजराज सिंह सोलंकी तथा वरिष्ठ सहायक श्री कालू राम वैरवा की ड्यूटी प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक लगाई गई है।

पुरी-अंगुल मेमो पर आग लगी

मनोरंजन सासमल, ओड़िशा, भुबनेस्वर: पुरी-अंगुल मेमो पर आग लगी। एलजीटी पर पता चला और पायलट ने समझदारी से उसे बुझा दिया। कुछ दिन पहले भी आग लगी थी। बार बार ट्रेन मे इसी प्रकार इंन्सिडेंट हो रहा है।

मंथन द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी संजय एम तराणेकर के मुख्य आतिथ्य व डॉ मनीष दवे के संचालन में सम्पन्न.

परिवहन विशेष न्यूज

मंथन साहित्यिक परिवार द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी डॉ शिवदत्त शर्मा जयपुर की अध्यक्षता व संजय एम. तराणेकर के मुख्य आतिथ्य तथा डॉ मनीष दवे, इंदौर के संचालन में संपन्न हुई. बच्चूलाल दीक्षित द्वारा सरस्वती वंदना, प्रो. राम पंचभाई, यवतमाल की मराठी में गणेश वंदना के साथ काव्य पाठ प्रारंभ हुआ.

प्रथमतः सुभाषचंद्र शर्मा जयपुर ने गा रही है गान जिंदगी छेड़ रही है तान जिंदगी इस नवीन गीत के साथ जिंदगी को परिभाषित करने वाले सस्वर गीत की प्रस्तुति दी. जिस पर गिरीश पाण्डेय ने प्रशंसात्मक मधुर भाव प्रकट किए. महेश गुप्ता राही ने सावन पावन प्यार का मौसम है, अमुआ की डाली पर बैठी कोयल की मधुर तान का मौसम. समीक्षा मधु पुरोहित ने की. इंजीनियर एन सी खंडेलवाल हास्य व्यंगकार द्वारा प्रस्तुत रचना जिंदगी तुझसे गिला नहीं, गिला उससे है जो जिंदगी में मिला नहीं कहते हैं कि जोडे.ऊपर से बनकर आते, लगता है मेरा जोडा.बनाया ही नहीं. जिंदगी की इस प्रस्तुति को डॉ टी महादेवराव व प्रो.राम पंचभाई ने खूब सराहा. गीता उनियाल ने मन की वेदना इन पंक्तियों के साथ मन की मुसीबत को जरूर बताइए, थककर न बैठो ये मंजिल के मुसाफिर इस पर प्रतिक्रिया प्रो.राम पंचभाई ने दी. गीतकार बृज व्यास शाजापुर के गीत के बोल स्वाधीनता सस्ती नहीं यह मांगती बलिदान है. कुछ सिंह निकले माद से आक्रोश को अपने जगा, सोया हुआ जो तंत्र था वो कांपने कैसे लगा. समीक्षा सुभाषचंद्र शर्मा ने उसी शैली में की.

डॉ. टी. महादेव राव विशाखापट्टनम ने आफताब शीर्षक के बोल- अजीब बसर है यारो इस शहर के सब हैं आफताब, खोज रहा है कब से खुशियों को इंसा वो जाने कहां छुप गए हैं डर के डॉ शिवदत्त शर्मा की प्रतिक्रिया इन शब्दों में- जिंदगी में जो जीना है मुस्कराइये, दिल के छाले दबा कर भी गुनगुनाइये. रेखा राठौर, सुसनेर की अभिव्यक्ति रक्षाबंधन पर रेशम की ये डोरी भाई जिसका न कोई मोल रे...जिसे प्रतिभा पुरोहित व बृज व्यास ने सराहा. प्रो. राम पंचभाई ने सफर की साथी राह का चित्रण इस पंक्ति के साथ मुश्किल से मंजिल को मैं सफर बनाने निकला हूँ. जिस पर महेश गुप्ता राही ने अपना विचार रखा. प्रतिभा पुरोहित अहमदाबाद ने बंगला देश की ज्वलंत समस्या पर कलम गिरी अंगारों से उद्घोष किया. रेखा राठौर ने भावनात्मक प्रतिक्रिया दी. महेन्द्र भट्ट व्यंगकार, ग्वालियर ने अपने चिरपरिचित मुद्रा में इन पंक्तियों के साथ प्रस्तुति दी - आ गया फिर आज मौसम अंगारों की तरह, इनका साथ सुभाषचंद्र शर्मा ने दिया. मुख्य अतिथि संजय एम तराणेकर की प्रस्तुति में कोलकाता में प्रशिक्षु डाक्टर की नृशंस हत्या के संदर्भ में रहीं योनि के भस्मासुर शीर्षक से देते हुए उन पापियों को सजा हो वस्त्रहीन उम्रकैद जैसी हो. का आह्वान किया. जिस पर महेन्द्र भट्ट ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी.

कार्यक्रम के संचालक डॉ. मनीष दवे ने भैया मेरे राखी बंधन को निभाने का वायदा लिया. इस तरह बहन पूछे क्या भैया एक वायदा निभाओगे, तुम हरदम मेरा साथ देना. इस पर संजय एम तराणेकर की वात्सल्य भाव की प्रतिक्रिया का अद्भुत संगम रहा. बच्चूलाल दीक्षित की रचना उपरांत डॉ शिवदत्त शर्मा का सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ. अंत में प्रो.राम पंचभाई ने मंचासीन कवियों की प्रस्तुतियों की संक्षिप्त समीक्षा करते हुए सभी का आभार माना.

बदलापुर स्टेशन पर रेल रोको प्रदर्शन, 15 ट्रेनों का रूट डायवर्ट; दस घंटे बाद शुरू हुआ परिचालन

परिवहन विशेष न्यूज

बदलापुर में दो स्कूली छात्राओं के यौन शोषण के विरोध में रेल रोको प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की वजह से 15 ट्रेनों के का रूट डायवर्ट किया गया। प्रदर्शन की वजह से अंबरनाथ-कारजात सेक्शन पर लोकल ट्रेन सेवाओं को 10 घंटे के लिए निलंबित किया गया।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में दो स्कूली छात्राओं के यौन शोषण के विरोध में रेल रोको प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की वजह से 15 ट्रेनों के का रूट डायवर्ट किया गया। इसके अलावा प्रदर्शन की वजह से अंबरनाथ-कारजात सेक्शन पर लोकल ट्रेन सेवाओं को 10 घंटे के लिए निलंबित किया गया। इस वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। आखिरकार पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने के 10 घंटे बाद रेल सेवाएं बहाल की गईं।

महाराष्ट्र के बदलापुर में क्या हुआ था?

बदलापुर पूर्व के एक नामी स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके में रोष व्याप्त कर दिया है। बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप स्कूल टॉयलेट साफ करने वाले व्यक्ति अक्षय शिंदे पर लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों में से एक चार साल की है और दूसरी छह साल की है। यह घटना 12 और 13 अगस्त को घटी थी।

18वां रामरसोड़ा शुरू, 200 पैदल यात्रियों का जत्था भी रामदेवरा के लिए निकला

-भादो मास में बाबा रामदेव के यहां दर्शन करने जाने वाले यात्रियो के लिए धर्म तालाब की पाल पर रामदेव सेवा समिति द्वारा चाय, पानी व जलपान और रात्रि विश्राम हेतु विगत 17 वर्षों से भव्य रामरसोड़ा लगाया जाता रहा हैं।

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा बागोर रामदेव सेवा समिति के सौजन्य से एवं समस्त ग्रामवासी बागोर द्वारा बागोर रायपुर मार्ग पर स्थित धर्म तालाब की पाल पर भाद्रपद माह के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन रामदेव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों की उपस्तिथि में माँण्डल विद्यायक उदय लाल भडाणा के प्रतिनिधि लाल चंद सेन के मुख्यातिथ्य व बागोर सरपंच कालु राम जाट के विशिष्ठ आतिथ्य में 18वें रामरसोड़े का भव्य शुभारम्भ किया गया।

संरक्षक जगदीश चन्द्र रेगर ने बताया कि करेड़ा रोड़ स्थित धर्म तालाब के पास राम रसौड़ा स्थल पर प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा पर राम रसोड़े का विगत 17 वर्षों से विशाल राम रसोड़े का आयोजन रामदेव सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ताओ द्वारा किया जाता रहा हैं। इसी कड़ी में इस बार के 18वें राम रसौड़े का बाबा रामदेव जी के छायाचित्र पर तिलक व माल्यार्पण के साथ ही दीप प्रज्वलित करके बाबा रामदेव जी का निशान (ध्वजा) का ध्वजारौहण करके क्षेत्रीय विधायक भडाणा के प्रतिनिधि लालचंद सेन ने भव्य शुभारंभ किया।

संरक्षक रेगर ने बताया कि आज शुरू हुए रामरसोड़े में रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए चाय, पानी व जलपान से साथ ही रात्रि विश्राम की भी सुविधाएं रामदेव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क आयोजित की जाएगी।

इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह राणावत, रामराय सेठिया, हरिकिशन बसवाल, राकेश सेन, मनीष कुमार शर्मा, पंचायत समिति सदस्य हरीश कुमार चंदेल, उपसरपंच घनश्याम सिंह देवपुरा, बक्षुराम गुर्जर, सुरेश जाट, हेमंत शर्मा, दुर्गेश कुमार स्वर्णकार, भैरुलाल उज्जैनिया, कालूराम दूरियां, अध्यक्ष चांदमल भोजपुरिया, महामंत्री नरेश कुमार मुंडेतिया, पुष्कर भोजपुरिया, उपाध्यक्ष राकेश दूरियां, राधेश्याम भोजपुरिया, रतन लाल भोजपुरिया, पप्पू उज्जैनिया, रतन लाल सुखरिया, भेरूलाल रैगर सहित रामदेव सेवा समिति के सभी सदस्य व बागोर ग्रामवासी मौजूद थे।

-200 पैदल यात्रियों का निकला जत्था।

मंगलवार को रामरसोड़े के शुभारंभ के बाद वही से बाबा रामदेवजी के दर्शन करने हेतु पैदल जाने के लिए 200 श्रद्धालुओं का एक जत्था रामदेवरा के लिए रवाना हुआ। जिसका रामदेव सेवा समिति द्वारा संचालित रामरसोड़ा स्थल से यात्रियों के मस्तक पर तिलक लगा माला पहना दही व गुड़ खिलाके मुंह मीठा करवाकर सुगन रस्म अदायगी करते हुए विधायक प्रतिनिधि एवं संरक्षक जगदीश रेगर ने हरी झंडी दिखा रामदेवरा पद यात्रियों के जत्थे

को रवाना किया। जिसमें रामप्रसाद माली, पवन माली, सरवन रेगर, दिलीप रेगर, राधेश्याम रेगर, चुन्नीलाल रेगर, प्रकाश रेगर सहित अन्य यात्री भी सामिल हैं।

-विशाल चौथा रक्तदान शिविर 23 को।

संरक्षक जगदीश चन्द्र रेगर ने जानकारी देते हुए बताया की पिछले 3 वर्षों से राम रसोड़े के कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन भी रामदेव सेवा समिति के बैनर तले किया जाता रहा हैं। ठीक उसी तरह इस वर्ष भी 23 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक चौथे रक्तदान का आयोजन भी रखा गया हैं।

तारा प्रसाद ने पूछा कि सुभद्रा योजना की एसओपी कहां है

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा, भुबनेश्वर: राज्य के हर परिवार की एक महिला को सुभद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र में यह बात छपी थी। राज्य में सरकार गठन के पहले दिन 12 जून की शाम को हुई पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, एसओपी इस बात की स्पष्ट तस्वीर के बाद आएगी कि सुभद्रा योजना के तहत किसे पैसा मिलेगा और किसे नहीं, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने कहा। 15 अगस्त को एसओपी आने के बाद सुभद्रा को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। हालाँकि, उच्च जाति के लोगों को इससे बाहर रखा जा सकता है। विशेष रूप से, यह माना गया कि सरकार उन लोगों को बाहर कर सकती है जो आयकर का भुगतान कर रहे थे। अभी तक एसओपी नहीं आई है। जिसे लेकर कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद भागरपति ने सवाल उठाया है। तारा प्रसाद ने पूछा कि सुभद्रा योजना की एसओपी कहां है तो उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री ने घोषणा की है कि सुभद्रा योजना की एसओपी 15 अगस्त को आयेगी। लेकिन 15 अगस्त को राक्षी पूर्णिमा ला दी गई लेकिन विभाग के पास सुभद्रा योजना एसओपी नहीं थी। सुभद्रा योजना एसओपी के क्षेत्र में वैसा ही कर रही है जैसे मजूरिया को आज नहीं तो कल बताया जा रहा है। राज्य सरकार को तुरंत सुभद्रा योजना एसओपी लानी चाहिए अन्यथा कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी तारा ने कहा।

'सोलन की महापौर को अयोग्य ठहराना भेदभाव', शीर्ष अदालत ने नई चुनाव प्रक्रिया पर लगाई रोक

शीर्ष अदालत ने वर्तमान महापौर उषा शर्मा को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को भेदभाव करार दिया है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुईयां की पीठ ने उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन के महापौर पद के लिए होने वाली नई चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने वर्तमान महापौर उषा शर्मा को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को भेदभाव करार दिया है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुईयां की पीठ ने उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर की अयोग्यता को जारी रखा गया था शीर्ष अदालत ने कहा, 'ऐसा लगता है कि यह भेदभाव का मामला है। एक महिला को नगर निगम के सदस्यों द्वारा महापौर पद के लिए चुना गया और एक पुरुष उम्मीदवार हार गया। इसलिए सभी पुरुष एकजुट हो गए।' अदालत ने कहा कि ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में भेदभाव होगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मेयर और नगर परिषद के सदस्यों के लिए सरकार द्वारा घोषित की गई नई चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023